RAJHIN/2014/55262

sancharjagat.com

खबरों व विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें
संचार जगत
मो.नम्बरः- +917357161599

संचार जगत

दैनिक समाचार पत्र

sancharjagat.com | editorial@sancharjagat.com

'सोच को इतना बड़ा रखो कि असफलता भी एक छोटा कदम लगे। सफलता कोई मंजिल नहीं, यह एक दिशा है। बड़ा सोचो, बड़ा करो।'

वर्षः 13 | अंकः 269 | जयपुर, बुधवार, 28 अक्टूबर , 2026 | मूल्यः 2.00 रूपए | पृष्ठः 8

ओरा वरमानी ने मलेशिया में बढ़ाया भारत का मान

अंतरराष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में हासिल की बड़ी सफलता, 'मिस राजस्थान 2024' से शुरू हुआ था सफर

'मिस ओरिएंट टूरिज्म ग्लोबल 2026' में बनीं फर्स्ट रनर-अप

संचार जगत

जयपुर। भारतीय मॉडल ओरा वरमानी ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर शानदार उपलब्धि हासिल करते हुए देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। मलेशिया के मलेका में आयोजित प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता 'मिस ओरिएंट टूरिज्म ग्लोबल 2026' में ओरा ने फर्स्ट रनर-अप (प्रथम उपविजेता) का खिताब अपने नाम किया। उनकी इस उपलब्धि को उनके मॉडलिंग सफर की एक महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है। ओरा ने कम उम्र में अपनी प्रतिभा, आत्मविश्वास और मेहनत के दम पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। उनकी इस उपलब्धि से परिवार और शुभचिंतकों में खुशी का माहौल है।





'मिस राजस्थान 2024' से शुरू हुआ सफर

ओरा वरमानी के पेजेंट सफर की शुरुआत 'मिस राजस्थान 2024' प्रतियोगिता से हुई थी। इस प्रतियोगिता में उन्होंने टॉप-14 फाइनलिस्ट में जगह बनाई थी। साथ ही उन्हें 'बेस्ट पर्सनैलिटी' का प्रतिष्ठित सब-टाइटल भी मिला था।

इस उपलब्धि ने उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता से शुरुआत करने के बाद ओरा ने अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार प्रयास किए और अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

बचपन का शौक बना जुनून- ओरा वरमानी ने बताया कि उन्हें बचपन से ही सजने-संवरने, कैमरे के सामने आने और मॉडलिंग करने का शौक था।

धीरे-धीरे उनका यह शौक जुनून में बदल गया और उन्होंने इसे अपने करियर के रूप में आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। ओरा के अनुसार, उन्हें अलग-अलग संस्कृतियां आकर्षित करती हैं। विभिन्न देशों की परंपराओं, पहनावे और सांस्कृतिक विविधताओं को जानने में उनकी विशेष रुचि है। अंतरराष्ट्रीय मंच पर भागीदारी ने उन्हें अलग-अलग संस्कृतियों को करीब से समझने का अवसर भी दिया।

परिवार के सहयोग को दिया सफलता का श्रेय

अपनी इस उपलब्धि का श्रेय ओरा वरमानी ने अपने परिवार के अटूट समर्थन और देशवासियों की शुभकामनाओं को दिया। उन्होंने बताया कि परिवार के प्रोत्साहन ने उन्हें अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ने की ताकत दी। मलेशिया में आयोजित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में फर्स्ट रनर अप का खिताब हासिल करना ओरा के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उनकी सफलता उन युवाओं के लिए भी प्रेरणा है, जो अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ओरा वरमानी की यह उपलब्धि भारतीय प्रतिभा की अंतरराष्ट्रीय मंच पर मौजूदगी को दर्शाती है और उनके मॉडलिंग करियर में आगे की संभावनाओं के नए रास्ते खोलती है।

तमिलनाडु की राजनीति में 'गरमी'

सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए, कानून ठप

नई दिल्ली/संचार जगत



तमिलनाडु की राजनीति में अन्नाद्रमुक के महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी और द्रमुक के अध्यक्ष एमके स्टालिन के बीच अक्सर तीखी जुबानी जंग और राजनीतिक तकरार बढ़ी है।

थेनी जिला उप-जेल से 17 कैदियों के फरार होने के मामले पर दोनों नेताओं ने सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं और इसे कानून-व्यवस्था की नाकामी बताया है।

पलानीस्वामी ने राज्य में बढ़ते अपराधों, बच्चों के लापता होने और हत्या की घटनाओं को लेकर स्टालिन के नेतृत्व वाली तत्कालीन कानून-व्यवस्था पर तीखा हमला बोला।

तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के प्रचार के दौरान पलानीस्वामी ने स्टालिन सरकार को 'विफलता का मॉडल' बताया। उन्होंने रोजगार, चेन्नई बाढ़ प्रबंधन और बढ़ते कर्ज को लेकर द्रमुक शासन को घेरा।

मृत्युंजय महादेव सद्गुरु आश्रम में संगीतमय सत्संग 1 कों

संचार जगत



टोंक। धर्म, अध्यात्म और सनातन संस्कृति के प्रति जनजागरण के उद्देश्य से शहर के जयपुर-कोटा मार्ग स्थित एनएच-52 पर सवाई माधोपुर पुलिया के पास नवनिर्मित मृत्युंजय महादेव सद्गुरु आश्रम में एक नवंबर को संगीतमय दिव्य आध्यात्मिक संवाद एवं सत्संग का आयोजन होगा। इसमें रामकथा मर्मज्ञ एवं भक्ति-अध्यात्म के प्रवक्ता महेश दत्त रामायणी श्रद्धालुओं को रामभक्ति, आध्यात्मिक ज्ञान और सनातन संस्कृति के विभिन्न पहलुओं से रूबरू कराएंगे। आश्रम के संस्थापक ज्योतिषाचार्य गुरुदेव पंडित राजकुमार शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम दोपहर दो बजे से प्रारंभ होगा। सत्संग में रामकथा के विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से भक्ति, शांति, सद्विचार और जीवन-मूल्यों की महत्ता पर प्रकाश डाला जाएगा। संगीतमय प्रस्तुतियों और आध्यात्मिक संवाद के जरिए श्रद्धालुओं को प्रभु श्रीराम के आदर्शों, रामनाम की महिमा तथा सनातन संस्कृति की शिक्षाओं को समझने का अवसर मिलेगा।

राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने के दिए निर्देश

झुंझुनूं जिले की 6 पंचायत समितियों के लिए मतदान दल हुए रवाना स्वीप गतिविधियों की सराहना कर अधिक मतदान की अपील

संचार जगत

जयपुर। पंचायतीराज आम चुनाव-2026 के तहत जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों को लेकर मंगलवार को सेठ मोतीलाल कॉलेज, झुंझुनूं में मतदान दलों का द्वितीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने प्रशिक्षण के बाद मतदान दलों को रवाना किया तथा चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने मतदान दलों को संबोधित करते हुए कहा कि आयोग की ओर से निर्वाचन संबंधी सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। अब चुनाव कार्य में लगे सेक्टर मजिस्ट्रेट, एरिया मजिस्ट्रेट, मतदान दलों सहित सभी कार्मिकों की जिम्मेदारी है कि वे उन्हें सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन पूरी सजगता, निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ करें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में निर्धारित दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए, ताकि चुनाव शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सकें। उन्होंने मतदान दलों को उनकी जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहने तथा किसी भी परिस्थिति में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया।साथ ही जिले में मतदाता जागरूकता के लिए संचालित स्वीप गतिविधियों की सराहना की और आमजन से लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की।

निकाय चुनाव की सफलता का पूरा श्रेय कार्मिकों को दिया



राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि निर्वाचन संबंधी समस्याओं एवं शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। किसी भी समस्या की शिकायत कंट्रोल रूम में दर्ज करवाई जा सकती है, जिस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

कार्मिकों को दिया श्रेय- राजेश्वर सिंह ने मतदान दलों को संबोधित करते हुए कहा कि निकाय चुनाव की सफलता का पूरा श्रेय आपको है। उन्होंने कहा कि आपकी कर्तव्यनिष्ठा के बिना यह संभव नहीं था। प्रशिक्षण के बाद मतदान दलों को आवश्यक दिशा-निर्देशों के साथ उनके निर्धारित मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ अरुण गर्ग, पर्यवेक्षक डॉ गौरव चतुर्वेदी, पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सिंह सागर, स्वीप के राज्य प्रभारी प्रो सुधीर सोनी एवं अति जिला कलक्टर परशुराम धानका भी उपस्थित रहे।

मतदान केंद्रका किया निरीक्षण-इसके बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने मंगलवार को झुंझुनूं जिले के हेतमसर एवं वाहिदपूरा में मतदान केंद्र का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और मतदान के लिए व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया।

पैसे देकर चलाया गया था ई20 के खिलाफ अभियान

नई दिल्ली, आरएनएन। इथेनॉल मिक्स पेट्रोल यानी ई 20 पर हाल में खासकर सोशल मीडिया पर काफी बवाल मचा था। कई लोगों ने शिकायत की थी इससे गाड़ियों का इंजन खराब हो रहा है और माइलेज पर भी असर पड़ रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया दावा

नितिन गडकरी ने आज कहा कि पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिलाने को लेकर विरोध पैसे देकर चलाया गया अभियान था।

गडकरी ने सीआईआई के एक कार्यक्रम में कहा, तीन महीने पहले ई20 ईंधन के खिलाफ काफी शोर मचाया गया था। अब ई20 ईंधन को लेकर नाराजगी खत्म हो गई है, यह पैसे देकर चलाया गया अभियान था। गडकरी ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन अधिसूचित किए जाने के एक दिन बाद यह टिप्पणी की है।

प्रेगनेंट पत्रकार को धक्का देने के आरोप में राहुल को नोटिस

नई दिल्ली, आरएनएन। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक 3 महीने की गर्भवती पत्रकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को नोटिस जारी कर दिया है। गर्भवती पत्रकार का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट तक मार्च के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उन्हें धक्का दिया था जिससे उन्हें गंभीर चोटें आ गईं और अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। मामले पर सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने सीजेआई सूर्यकांत के सामने गर्भवती महिला पत्रकार की याचिका का मौखिक रूप से उल्लेख किया जिसके बाज पीठ ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का आदेश जारी कर दिया। महिला पत्रकार की याचिका में कहा गया कि प्रतिवादी नंबर 4 राहुल गांधी ने अचानक उन्हें गेट की तरफ काफी जोर से धक्का मारा जिससे वह गिर गईं।

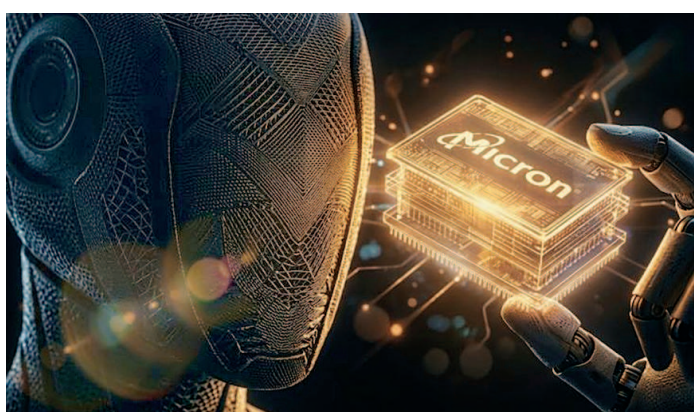
रिसर्च काउंटरपॉइंट की रिपोर्ट के अनुसार, 2030 तक ह्यूमनॉइड रोबोट के कारण रैम की मांग 20 गुना बढ़ेगी

अब रोबोट्स के लिए बढ़ेगी धरती पर रैम की डिमांड

नई दिल्ली/संचार जगत

एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) डेटा सेंटरों की मांग के कारण मेमोरी चिप्स इन दिनों सबसे ज्यादा मांगी जाने वाली चीज बन गई हैं। इस कारण लगातार स्मार्टफोन समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के दाम बढ़ते जा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि जल्द ही यह दौर थमने वाला है तो ऐसा नहीं है।

एक्स के मालिक एलन मस्क का कहना है कि जब दुनिया में ह्यूमनॉइड रोबोट यानी इंसान जैसे दिखने वाले रोबोट का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू होगा, तो स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी। इसका मतलब है कि मस्क साफ तौर पर कहना चाह रहे हैं कि रैम और मेमोरी चिप्स की मांग अभी आगे आने वाले समय में और भी बढ़ने वाली है। मस्क ने कहा है कि रोबोट की रैम की जरूरतें धरती पर बाकी सब चीजों से ज्यादा होंगी यानी इसकी डिमांड सबसे ज्यादा होगी। एलन मस्क ने एक्स पर एक थ्रेड का जवाब देते हुए मेमोरी चिप की बढ़ती मांग के बारे में बताया है।



बता दें कि थ्रेड में काउंटरपॉइंट रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आने वाले सालों में कंप्यूटर मेमोरी की मांग बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। रिपोर्ट बताती है कि इंसानों की तरह दिखने वाले रोबोट्स की वजह से दुनियाभर में रैम की जरूरत 20 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाएगी। जहां साल 2026 में इसके लिए लगभग 8,300 टीबी रैम की जरूरत होगी, वहीं साल 2030 तक यह बढ़कर करीब 1,72,000 टीबी हो जाएगी।

मस्क बोले, सुपर इंटेलिजेंस से ज्यादा होगी रोबोट की डिमांड

एलन मस्क ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। मस्क का मानना है कि भविष्य में रोबोट की RAM की जरूरतें धरती पर बाकी सब चीजों से ज्यादा होंगी। उन्होंने लिखा कि यह बात बिल्कुल बेतुकी लगती है। रोबोट्स को रैम की सबसे ज्यादा जरूरत इसलिए होगी क्योंकि वे असली दुनिया में मौजूद रहकर चीजों को छू सकते हैं उन्हें आकार दे सकते हैं और काम कर सकते हैं। जबकि डिजिटल दुनिया की चीजें ऐसा नहीं कर सकतीं। इसका मतलब है कि मस्क का मानना है कि काउंटर पॉइंट की रिपोर्ट में बताए गए डेटा से भी ज्यादा रैम की मांग बढ़ेगी। सुपर इंटेलिजेंस की जरूरतें तो रोबोट्स से भी कहीं ज्यादा होंगी, लेकिन सुपर इंटेलिजेंस का लगभग 100 प्रतिशत कंप्यूटेशन गहरे अंतरिक्ष में बने सुपरकंप्यूटरों पर होगा। यह तो जाहिर सी बात है। बता दें कि एआई डेटा सेंटर की ओर से रैम की मांग ने इंडस्ट्री में थोड़ी हलचल मचा दी है। पिछले एक साल में रैम की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी हैं, जिसकी वजह से स्मार्टफोन और लैपटॉप जैसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स भी महंगे हो गए हैं। ऐसा सिर्फ फोन बनाने वाली कंपनियों के साथ ही नहीं हुआ है, बल्कि भारतीय कारोबारों को भी रैम की कमी की मार झेलनी पड़ी है।

मेरी किताब आएगी तो तमाशा होना तय

सोनिया बोलीं- मेरी कहानी दूसरों ने खूब सुनाई, अब मेरी बारी है

नई दिल्ली, आरएनएन। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की 10 नवंबर को किताब आने वाली है। उससे पहले वह अपनी पुस्तक के बारे में छोटे-छोटे अंशों में जानकारियां दे रही हैं या फिर प्रचार भी कर रही हैं। इस बीच उन्होंने एक बार फिर से एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है और कहा कि अब अपनी कहानी खुद सुनाने की बारी है।



इस वीडियो के साथ कैप्शन में उन्होंने लिखा है, यह किताब जब आएगी तो कुछ तमाशा होना तय है। आखिर दशकों तक दूसरे लोगों ने मेरी कहानी सुनाई थी, अब मेरी बारी है। जब मैं खुद अपनी कहानी दुनिया को बताऊंगी। इसके अलावा सोनिया गांधी ने वीडियो में बताया, मैं नहीं जानती कि मुझे पूरी कहानी बतानी चाहिए या नहीं। मेरे पति से जब प्रधानमंत्री बनने को कहा गया तो मैं इसके पूरी तरह खिलाफ थी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त एक्शन

सुशासन, पारदर्शिता, प्रशासनिक जवाबदेही के लिए की गई कड़ी कार्रवाई

17 सेवारत अधिकारियों की रोकी 2 से 4 वार्षिक वेतन वृद्धि,

16 सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन भी रोकी

संचार जगत



जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा अपराध करने या अपराध को बढ़ावा देने के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत राज्य सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई है। वृहद शास्ति(मेजर पेनल्टी) प्रकरणों के तहत 30 मामलों का निस्तारण करते हुए 17 सेवारत अधिकारियों की वार्षिक वेतन वृद्धियां तथा 16 सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन रोकने को मंजूरी दी गई है। इस कार्रवाई से सुशासन, पारदर्शिता, प्रशासनिक जवाबदेही, राजकीय संसाधनों के संरक्षण और लोकसेवा के दायित्वों के प्रति गंभीरता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।

आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों से सांठगांठ पर कार्रवाई

सेवारत अधिकारियों के मामलों में आरोपों की गंभीरता के अनुरूप 2 से 4 वार्षिक वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड का अनुमोदन किया गया है। जिसके तहत आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों से सांठगांठ तथा अवैध बजरी खनन से जुड़े माफिया से अनुचित लाभ प्राप्त करने के मामले में तत्कालीन वृत्ताधिकारी की 4 वार्षिक वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकने को मंजूरी दी गई।

समुचित अनुसंधान नहीं करने के मामले में तत्कालीन पुलिस निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक एवं कॉन्स्टेबल सहित संबंधित पुलिस टीम के अधिकारियों की लापरवाही प्रमाणित होने पर 3 अधिकारियों के विरुद्ध वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकी गई हैं। वहीं, मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों से निकटता रखने, मिलीभगत करने तथा इनामी अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करने के मामले में तत्कालीन वृत्ताधिकारी एवं कॉन्स्टेबल की 2-2 वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकी गई हैं।

पूंजी बाजार से निवेश जुटाने के लिए वितरण निगमों में अनुशासन जरूरी

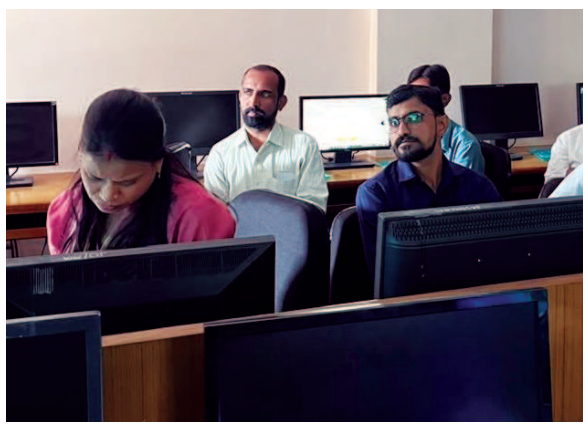
संचार जगत

जयपुर। डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट के सत्र DISCOMs Financial Transformation and Capital Market Readiness में बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने, पूंजी बाजार से निवेश जुटाने और संरचनात्मक सुधारों पर चर्चा हुई। सत्र का संचालन हिमांशु चावला ने किया। इसमें टीईआरसी के अध्यक्ष हेमंत वर्मा, ग्रिड इंडिया के पूर्व सीईओ एस.के. सूनी, बीईआरसी के सदस्य मनोज कुमार, पीएफसी के कार्यकारी निदेशक सौरव शाह और बीवाईपीएल के सीओओ संतोष कुमार ने विचार रखे।

विशेषज्ञों ने कहा कि पूंजी बाजार से निवेश के लिए पारदर्शी लेखांकन, नियमित वित्तीय खुलासा, मजबूत आंतरिक नियंत्रण, समयबद्ध टैरिफ और सब्सिडी भुगतान तथा बेहतर कॉरपोरेट गवर्नेंस जरूरी है।

जनगणना 2027 के द्वितीय चरण का कार्य प्रारंभ

42 प्रतिभागियों को 27 से 30 अक्टूबर तक दिया जा रहा गहन प्रशिक्षण



संचार जगत

जयपुर। जनगणना 2027 के द्वितीय चरण (जनसंख्या गणना) के कार्य के सफल संपादन हेतु जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 27 अक्टूबर 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण में जिले के प्रत्येक चार्ज जनगणना कार्यालय से नियमित सहायक एवं तकनीकी सहायक का दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला कलक्टर संदेश नायक के निर्देशानुसार मंगलवार 27 अक्टूबर से एस.एस. जैन सुबोध पी.जी. कॉलेज, रामबाग सर्किल, जयपुर में प्रारंभ किया गया। संयुक्त निदेशक सांख्यिकी विभाग बाबूलाल मीणा ने बताया कि जनगणना कार्य निदेशालय के अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण में जनगणना के द्वितीय चरण के सम्पादन हेतु नियमित सहायक एवं तकनीकी सहायकों को गहन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रथम बैच में 42 प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया जा रहा हैं।

भारतीय ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करें युवा, साहित्य को समृद्ध बनाने में निभाएं भूमिका : राज्यपाल

राज्यपाल ने रैफल्स यूनिवर्सिटी में अंतरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सव के समापन समारोह को किया संबोधित

संचार जगत



जयपुर/कोटपूतली-बहरोड़। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा, साहित्य और सांस्कृतिक विरासत विश्वभर में अपनी विशिष्ट पहचान रखती है। युवाओं को भारतीय बौद्धिक परंपराओं से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान और कौशल को विकसित करना चाहिए तथा राष्ट्र के विकास के साथ साहित्य एवं संस्कृति को समृद्ध बनाने में योगदान देना चाहिए। राज्यपाल बागडे मंगलवार को रैफल्स यूनिवर्सिटी, नीमराना में आयोजित तीन दिवसीय 'वर्ड्स बियॉन्ड बॉर्डर्स' (डब्ल्यूबीबी) अंतरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सव-2026 के समापन समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साहित्यिक विरासत और सांस्कृतिक मूल्यों की महत्ता रेखांकित करते हुए कहा कि भारत प्राचीन काल से ही ज्ञान-विज्ञान का प्रमुख केंद्र रहा है। यहां की बौद्धिक परंपराओं ने विश्व को दिशा देने का कार्य किया है। राज्यपाल ने भारतीय गणितीय ज्ञान का उल्लेख करते हुए कहा कि शून्य और दशमलव पद्धति भारत की महत्वपूर्ण देन हैं, भारतीय प्राचीन ग्रंथों, वेदों और उपनिषदों में निहित ज्ञान आज भी प्रासंगिक है। भारत की ज्ञान परंपरा और साहित्य का प्रभाव देश की सीमाओं से परे विश्व के अनेक देशों तक पहुंचा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान वीरता की भूमि होने के साथ-साथ साहित्य, कला और संस्कृति की भी समृद्ध धरोहर है। यहां के किले, महल और ऐतिहासिक इमारतें केवल स्थापत्य कला के उदाहरण नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक चेतना और गौरवशाली इतिहास की जीवंत अभिव्यक्ति हैं। उन्होंने भारतीय साहित्य की वैश्विक प्रतिष्ठा का उल्लेख करते हुए रवीन्द्रनाथ टैगोर की साहित्यिक कृतियों तथा जर्मन भाषाविद् एवं साहित्यकार मैक्स मूलर द्वारा भारतीय साहित्य के अनुवाद के माध्यम से भारतीय ज्ञान को विश्व तक पहुंचाने में निभाई गई भूमिका पर प्रकाश डाला।

पंचायतीराज चुनाव के दौरान मतदान दिवस पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में रहेगा

संचार जगत

जयपुर। पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के तहत जयपुर जिले में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य तथा पंच-सरपंच पदों के निर्वाचन के लिए निर्धारित मतदान तिथियों पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) संदेश नायक ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम एवं समय-सारणी में संशोधन के अनुसार जयपुर जिले में चार चरणों में मतदान की तिथियां निर्धारित की गई हैं।

प्रथम चरण का मतदान संपन्न होने के उपरांत द्वितीय चरण में जिला परिषद् एवं पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए 28 अक्टूबर तथा पंच-सरपंच पदों के लिए 30 अक्टूबर को मतदान होगा। तृतीय चरण में सदस्य पदों के लिए 3 नवंबर तथा पंच-सरपंच पदों के लिए 5 नवंबर को मतदान होगा। इसी प्रकार चतुर्थ चरण में सदस्य पदों के लिए 14 नवंबर तथा पंच-सरपंच पदों के लिए 16 नवंबर को मतदान होगा। उन्होंने बताया कि मतदान दिवस पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित समस्त सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालयों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

साथ ही परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 के अंतर्गत भी मतदान दिवस पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा, ताकि इन क्षेत्रों के मतदाता मतदान कर सकें। पुनर्मतदान की स्थिति में भी जिन मतदान क्षेत्रों में पुनर्मतदान होगा, वहां पुनर्मतदान की तिथि को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान दिवस पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत सभी कार्मिकों, जिनमें आकस्मिक कामगार भी सम्मिलित हैं, को सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाएगा, ताकि वे अपने मताधिकार का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से उपयोग कर सकें।

स्मार्ट मीटरिंग से बिजली उपभोक्ताओं को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं, डेटा एनालिटिक्स से विद्युत वितरण व्यवस्था होगी

संचार जगत

स्मार्ट मीटरिंग से सेवाओं में सुगमता एवं उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ

जयपुर। डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट (DUM-2026) में आयोजित 'डिजिटल इंटेलिजेंस और एडवांस्ड स्मार्ट मीटर डेटा एनालिटिक्स' विषयक सत्र में स्मार्ट मीटरिंग के प्रभाव, डेटा आधारित निर्णय प्रणाली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग (ML) तथा विद्युत वितरण कंपनियों के समक्ष मौजूद तकनीकी एवं व्यावसायिक चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। सत्र की अध्यक्षता इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम (आईएसजीएफ) के अध्यक्ष रेजी कुमार पिल्लई ने की। विशेषज्ञों ने कहा कि स्मार्ट मीटरिंग के माध्यम से एकत्रित डेटा का उचित विश्लेषण कर व्यावहारिक एवं उपयोगी निष्कर्ष प्राप्त किए जा सकते हैं, जिनके आधार पर बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी रणनीतियां तैयार की जा सकती हैं।

सत्र में अनिल दौलानी, सीनियर पार्टनर, पे लोकल, श्री अनिमेष, हेड सीईओ सेल सीपीडीएल, श्री आर.एस. सेल्वम, उपाध्यक्ष, स्टेलमेक लिमिटेड, बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट अमित तोमर, चंडीगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (CPDL) में सीईओ सेल (CEO Cell) के प्रमुख अनिमेष और आईएसजीएफ के अध्यक्ष अजय राजानी ने भाग लिया। विशेषज्ञों ने बताया कि कई राज्यों में स्मार्ट मीटरिंग एवं आधुनिक तकनीक के उपयोग से नए बिजली कनेक्शन जारी करने, बिलों के भुगतान तथा शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया को अधिक सरल और सुविधाजनक बनाया गया है।

तकनीक आधारित सेवाओं से उपभोक्ताओं को बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के कार्यालयों में बार-बार जाने की आवश्यकता कम हुई हैद्य इसके साथ ही बिलिंग एवं भुगतान प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने और शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने में भी सहायता मिली है।

डेटा एनालिटिक्स, साइबर सुरक्षा एवं तकनीकी तैयारी पर जोर- सत्र में ओरेकल यूटिलिटीज के निदेशक संतोष नायर, रेडियस सिनर्जी के सलाहकार जयदीप सिंह, इंटेलीस्मार्ट के मुख्य प्रौद्योगिकी एवं रणनीति अधिकारी (सीटीओ एवं सीएसओ) गौतम कुमार तथा वर्कऑन ग्रिड के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (सीटीओ) आयुष अग्रवाल ने भी अपने विचार व्यक्त किए। विशेषज्ञों ने कहा कि स्मार्ट मीटरों से प्राप्त उपभोक्ता डेटा का निर्धारित नियमों, कानूनों एवं अधिकृत प्रक्रियाओं के अनुरूप विश्लेषण कर विद्युत सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने की रणनीतियां तैयार की जा सकती हैं। डिस्कॉम द्वारा स्मार्ट तकनीक के माध्यम से प्राप्त डेटा से बिजली की मांग का अधिक सटीक पूर्वानुमान लगाने, स्वचालित निर्णय लेने तथा उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप सेवाओं में सुधार करने में सहायता मिलेगी। स्मार्ट मीटरों से प्राप्त रियल-टाइम डेटा के उपयोग से विद्युत भार का बेहतर वितरण संभव होगा, जिससे उपकरणों पर अनावश्यक दबाव कम करने और उनके खराब होने की आशंका को कम करने में मदद मिल सकती है। बढ़ते विद्युत भार में निर्बाध एवं विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करने एवं इसमें नवीकरणीय ऊर्जा की भूमिका' सत्र में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष घनश्याम प्रसाद, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के सीएमडी रोहित गुप्ता, कैलिफोर्निया एनर्जी आयोग के वीसी सिवा गंडा तथा अन्य विशेषज्ञों ने भाग लिया।

अजमेर के दयानन्द बाल सदन में 10 लाख रुपए की लागत से निर्माण एवं जीर्णोद्धार कार्य का विधानसभा अध्यक्ष ने किया शुभारम्भ

संचार जगत



जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मंगलवार को अजमेर जिले के केसरगंज स्थित दयानन्द बाल सदन के बालगृह में विधायक कोष से 10 लाख रुपए की लागत से फर्श निर्माण एवं जीर्णोद्धार कार्य का शुभारम्भ किया। इस कार्य के पूर्ण होने से बालगृह में निवासरत बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी तथा उनके लिए सुरक्षित, स्वच्छ और सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

इस अवसर पर देवनानी ने कहा कि दयानन्द बाल सदन देश की पुरानी सेवाभावी संस्थाओं में से एक है। यह स्वयंसेवी संस्था अनाथ, निराश्रित, असहाय तथा खोए हुए बालक-बालिकाओं का निःशुल्क पालन-पोषण करने के साथ उन्हें शिक्षित एवं संस्कारित करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। संस्था के माध्यम से अनेक बच्चों को आत्मनिर्भर एवं समाजोपयोगी नागरिक बनाने में योगदान दिया गया है। संस्था द्वारा किए जा रहे सेवा कार्य सराहनीय हैं।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एवं संस्कारयुक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। विद्यालयों में भवन, अतिरिक्त कक्षा-कक्ष, प्रयोगशालाओं, खेल सुविधाओं तथा अन्य आवश्यक संसाधनों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान देना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में अच्छे संस्कार, अनुशासन, आत्मविश्वास और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करना भी है।

नशा तस्करों पर राजस्थान पुलिस का बड़ा प्रहार, 26 अक्टूबर तक 8,842 आरोपी गिरफ्तार

डीजीपी निर्देशन में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत व्यापक कार्रवाई

एक दिवसीय विशेष अभियान में 262 प्रकरण दर्ज, 278 आरोपी गिरफ्तार, 2.91 करोड़ के मादक पदार्थ जब्त

संचार जगत

जयपुर। राजस्थान को नशा मुक्त बनाने और मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा के निर्देशन में संचालित इस अभियान के तहत गत 26 अक्टूबर तक मादक पदार्थों से संबंधित 7,695 प्रकरण दर्ज कर 8,842 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस अवधि में 220 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार करने के साथ 335 हॉटस्पॉट पर छापेमारी की गई। पुलिस ने मादक पदार्थों की बरामदगी के साथ-साथ तस्करी से अर्जित अवैध संपत्तियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की है। इसी क्रम में 26 अक्टूबर को प्रदेशभर में एक दिवसीय विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान 262 प्रकरण दर्ज कर 278 आरोपियों





को गिरफ्तार किया गया। अभियान में 8 सरगनाओं एवं तस्करों को चिह्नित किया गया तथा 6 हॉटस्पॉट पर कार्रवाई की गई। व्यापक जांच अभियान के तहत 3,496 स्थानों की जांच की गई।

एक दिवसीय अभियान में नशे के 278 तस्कर-आरोपी गिरफ्तार, 2.91 करोड़ रुपये के मादक पदार्थ जब्त- 26 अक्टूबर को चलाए गए विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने 14.68 किलोग्राम अफीम, 365.33 किलोग्राम डोडा पोस्त, 65.74 किलोग्राम गांजा, गांजे के 124 पौधे, 352.82 ग्राम स्मैक, 112.78 ग्राम हेरोइन और 177.57 ग्राम एमडी बरामद की। इसके अतिरिक्त 1,717 नशीली गोलियां भी जब्त की गईं। अभियान के दौरान 4 लाख 98 हजार 105 रुपये नकद जब्त किए गए। बरामद मादक पदार्थों का अनुमानित मूल्य 2 करोड़ 91 लाख 18 हजार 247 रुपये है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 15 वाहन और 8 मोबाइल फोन भी जब्त किए। 26 अक्टूबर तक की कार्रवाई

अब तक 8,842 गिरफ्तार, 7,695 प्रकरण दर्ज

आंकड़ों के अनुसार 26 अक्टूबर 2026 तक मादक पदार्थों से संबंधित 7,695 प्रकरण दर्ज किए गए और 8,842 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसके अतिरिक्त फरार, हिस्ट्रीशीटर एवं इनामी श्रेणी के 220 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इस अवधि में 335 हॉटस्पॉट पर छापेमारी की गई।

1,244.20 करोड़ रुपये मूल्य के मादक पदार्थ बरामद

कुल कार्रवाई के दौरान राजस्थान पुलिस ने 1,010.55 किलोग्राम अफीम, 131.46 टन डोडा पोस्त और 274.13 किलोग्राम एमडी बरामद की। आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में बरामद मादक पदार्थों का कुल मूल्य 1,244.20 करोड़ रुपये है।

नशे के अवैध कारोबार के विरुद्ध लक्षित कार्रवाई करते हुए 35 एमडी फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ किया गया तथा अवैध खेती के विरुद्ध 144 स्थानों पर छापेमारी की गई। इस अवधि में 2,125 वाहन जब्त किए गए।

3.63 लाख से अधिक नागरिक अभियान से जुड़े-

राजस्थान पुलिस नशे के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ जनजागरूकता और जनभागीदारी पर भी जोर दे रही है। 26 अक्टूबर तक अभियान से 3,63,547 नागरिकों को जोड़ा गया। इनमें से 3,58,682 नागरिकों ने नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए शपथ ली। इस अवधि में 3,966 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

नशा मुक्त राजस्थान के लिए

तस्करों की अवैध संपत्तियों पर भी कार्रवाई

राजस्थान पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ी अवैध संपत्तियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की है। 26 अक्टूबर तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार संपत्ति संबंधी कार्रवाई के तहत 250 मामलों में 75 संपत्तियों पर कार्रवाई की गई। इनसे संबंधित संपत्ति का मूल्य लगभग 30.25 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-स्स के तहत 149 कार्रवाइयां की गईं तथा पीआईटी एनडीपीएस के तहत 101 प्रस्ताव तैयार किए गए। इन कार्रवाइयों का उद्देश्य नशा तस्करी से अर्जित अवैध संपत्तियों और इसके आर्थिक नेटवर्क पर अंकुश लगाना है।

विरासत से विकास तक, भारतीय ज्ञान परंपरा ही हमारी शक्तिः राज्यवर्धन राठौड़



संचार जगत

जयपुर। कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राजस्थान विश्वविद्यालय के राजस्थान अध्ययन केंद्र द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी राजस्थान का लोक साहित्य, कला एवं इतिहास के उद्घाटन समारोह किया। समारोह में युवाओं से संवाद करते हुए राठौड़ ने कहा कि भारत की विशेषता यह है कि उसने हर युग में समय के साथ कदम बढ़ाए हैं और अपनी सभ्यतागत चेतना को भी साथ लेकर चला है। युग और अभिव्यक्ति के माध्यम बदलते रहे, लेकिन ज्ञान परंपरा निरंतर आगे बढ़ती रही। साहित्य, लोककथाओं, लोकगीतों, कला और परंपराओं के माध्यम से एक पीढ़ी अपना अनुभव अगली पीढ़ी तक पहुंचाती रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की विविध बोलियां, लोक परंपराएं और सांस्कृतिक विशेषताएं हमारी समृद्ध विरासत का हिस्सा हैं। मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती और शेखावाटी की सांस्कृतिक पहचान के बावजूद एक साझा भाव हमें जोड़ता है। यही भारत की विशेषता है कि विविधताओं के बीच हमारी एकता और सांस्कृतिक निरंतरता बनी हुई है। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। भारत की असली ताकत अपनी विरासत को सहेजते हुए आधुनिकता के साथ आगे बढ़ने में है। उन्होंने युवाओं की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि भारत आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष तकनीक, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आधुनिक तकनीक को अपनी सभ्यतागत बुद्धि के साथ जोड़कर हम भारतीय भाषाओं, साहित्य और कला को नए माध्यमों से दुनिया तक पहुंचा सकते हैं।

प्रदेश में बेहतर रोड कनेक्टिविटी से विकास को मिली नई रफ्तार

संचार जगत



जयपुर। प्रदेश में गांवों से लेकर शहरों तक आमजन को सुगम आवागमन देने और आर्थिक गतिविधियों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी के दृष्टिकोण के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार सड़क विकास पर प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी का परिणाम है कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 37 हजार 527 करोड़ रुपये से अधिक व्यय कर 51 हजार 790 किलोमीटर लम्बी सड़कों का विकास किया गया है, जो प्रदेश में सड़क सम्पर्क के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भजनलाल शर्मा का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुसार विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए देश-प्रदेश में बेहतर सड़क सम्पर्क आवश्यक है। इस दिशा में तेजी से कार्य करते हुए वर्तमान सरकार ने कुल 18 हजार 917 किलोमीटर लंबाई की नई सड़कों के निर्माण पर 9 हजार 704 करोड़ रुपये से अधिक व्यय किए हैं। सितम्बर-अक्टूबर, 2026 के दौरान सभी 41 जिलों में सार्वजनिक निर्माण विभाग के 3 हजार 40 करोड़ रुपये की लागत वाले 1 हजार 763 कार्यों का शिलान्यास किया जा चुका है। वहीं, 371 करोड़ रुपये की लागत वाले 261 कार्यों का लोकार्पण भी किया गया है। सरकार ने ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए 23 हजार 952 किलोमीटर लंबाई के कार्यों पर 12 हजार 311 करोड़ रुपये से अधिक व्यय किए गए हैं। इसके तहत एक हजार 760 गांवों एवं 21 बसावटों को डामर सड़कों से जोड़ा गया है। इससे ग्रामीण आबादी को सुगम आवागमन के साथ ही कृषि, व्यापार और अन्य आर्थिक गतिविधियों में भी सुविधा मिल रही है। प्रदेश में सड़क नेटवर्क को अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए पुलों एवं रेलवे क्रॉसिंग पर आधारभूत संरचनाओं का विकास भी किया जा रहा है।

नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की समीक्षा बैठक आयोजित

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की समीक्षा समिति की 15वीं बैठक में वीसी के माध्यम से शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नर्मदा नहर परियोजना ने अंतरराज्यीय जल सहयोग के क्षेत्र में नई मिसाल पेश की है। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र भाई पटेल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस भी वीसी के जरिये उपस्थित रहे।

भंडारण सुविधाओं और कृषि यंत्र किराया केंद्रों की हुई समीक्षा

संचार जगत



जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार सहकार से समृद्धि की दिशा में किसानों को बेहतर भंडारण सुविधाएं उपलब्ध कराने और बाजार से जोड़ने के लिए कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सचिवालय में सहकारिता विभाग की विश्व की सबसे बडी अन्न भण्डारण योजना एवं एनसीओएल, एनसीईएल तथा बीबीएसएसएल की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने गोदामों के निर्माण और उपयोग, किसानों को किराये पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने तथा सहकारी समितियों की गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिये कि सहकारिता क्षेत्र में बनाए गए गोदामों का संचालन समय पर शुरू किया जाए ताकि किसानों को भंडारण की सुविधा मिल सके। उन्होंने राज्य के क्षेत्रवार विशेष उत्पादों यथा- सोजत की मेहंदी, बांरा का चावल, नागौर की मैथी एवं जीरा, मथानिया की मिर्च आदि को बढावा दिया जाकर विदेशों में निर्यात की संभावनाएं तलाशने के भी निर्देश दिए। बैठक में शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारिता डॉ. समित शर्मा ने बताया कि प्रदेश में इस योजना के तहत 130 गोदामों का निर्माण पूरा हो चुका है और 70 गोदामों का काम जारी है। इन गोदामों का उपयोग समर्थन मूल्य पर खरीदी गई उपज, राशन के अनाज, बीज और उर्वरकों के भंडारण में किया जा सकता है। समितियों द्वारा स्वयं उपयोग करने के साथ गोदामों को किराये पर देने के विकल्पों पर भी चर्चा हुई।

सब-इंस्पेक्टर भर्ती पेपर लीक मामला

जगदीश विश्नोई गैंग का इनामी पेपर सॉल्वर गिरफ्तार

संचार जगत



जयपुर। राजस्थान में चर्चित उप-निरीक्षक संयुक्त प्रतियोगी भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक मामले में स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। एसओजी ने पेपर लीक माफिया गिरोह के मुख्य सरगना जगदीश विश्नोई के लिए परीक्षा से ठीक पहले पेपर हल करने वाले 25 हजार रुपये के इनामी फरार आरोपी मनोहर लाल मांजू को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी सिरोही जिले के आबूरोड स्थित सेठ मंगलचंद राजकीय महाविद्यालय में लोक प्रशासन विषय का सहायक आचार्य है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एडीजी, एटीएस एवं एसओजी विशाल बंसल ने बताया कि उप-निरीक्षक भर्ती परीक्षा-2021 के पेपर लीक प्रकरण में यह महत्वपूर्ण गिरफ्तारी की गई है। मामले के सामने आने के बाद से ही आरोपी मनोहर लाल मांजू अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार फरार चल रहा था। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक प्रकरण में अब तक कुल 157 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अनुसंधान जारी है।

चांदी के वर्क की 30 हजार पन्नियां और 340 किलो काली मिर्च सीज

संचार जगत



जयपुर। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान के तहत त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और मिलावटखोरी पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए निरीक्षण एवं नमूनीकरण की कार्रवाई जारी है। खाद्य सुरक्षा टीम जयपुर प्रथम ने विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर नमूनीकरण की कार्रवाई की। इस दौरान चांदी के वर्क की 30 हजार पन्नियां और 340 किलोग्राम काली मिर्च सीज की गई। साथ ही विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जाँच के लिए भेजने की कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त अविचल चतुर्वेदी के निर्देश और जयपुर प्रथम के अभिहित अधिकारी डॉ. रवि शेखावत के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा टीम ने सीकर रोड स्थित कुकरखेड़ा मंडी में मोना एंड कंपनी का निरीक्षण किया। इस कार्रवाई के दौरान चांदी के वर्क की 30 हजार पन्नियां और 340 किलोग्राम काली मिर्च सीज की गई। अभियान के तहत टीम ने विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र स्थित मेट्रो कैश एंड कैरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का निरीक्षण कर काजू टुकड़ी और खरबूजे के बीज के नमूने लिए। वहीं, रिलायंस मार्ट से गुलाब जामुन, मसूर पाक, बादाम और घी के नमूने लिए गए। टीम ने कुकड़खेड़ा मंडी के रघु एंटरप्राइजेज से काजू के और मोना एंड कंपनी के यहां से चांदी के वर्क, काली मिर्च एवं पिस्ता कतरन के नमूने लिए।

राज्यपाल ने मोटरसाइकिलों को दिखाई झंडी



जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कोटपूतली-बहरोड़ जिले के नीमराणा स्थित हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के संयंत्र में राजस्थान पुलिस के लिए 30 मोटरसाइकिलों को झंडी दिखाकर रवाना किया। राइजिंग नीमराणा कार्यक्रम के तहत आयोजित इस पहल में राज्यपाल ने सहभागिता करते हुए सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों की पालना के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संदेश दिया। बागडे ने हीरो मोटोकॉर्प की ओर से सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत संचालित 'राइड सेफ इंडिया' कार्यक्रम के तहत राजस्थान पुलिस को मोटरसाइकिलें उपलब्ध कराने की पहल की सराहना की।

दुबई के लिए नई फ्लाइट शुरू



संचार जगत

जयपुर। जयपुर से दुबई जाने वाले यात्रियों के लिए यहां के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक नई फ्लाइट शुरू हो गई है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की इस नई सेवा से यात्रियों को अब सफर के लिए ज्यादा विकल्प मिलेंगे। यह फ्लाइट सप्ताह में तीन दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को संचालित होगी। फ्लाइट जयपुर से दोपहर एक बजे दुबई के लिए उड़ान भरेगी। वहीं, दुबई से आने वाली फ्लाइट रात 9 बजकर 10 मिनट पर जयपुर पहुंचेगी। अब तक इस रूट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की दैनिक फ्लाइट और स्पाइसजेट की सेवाएं उपलब्ध थीं। नई फ्लाइट शुरू होने से जयपुर और दुबई के बीच हवाई कनेक्टिविटी बढ़ने की उम्मीद है। इससे बिजनेस, नौकरी और घूमने के लिए दुबई जाने वाले यात्रियों को अपनी सुविधा के हिसाब से फ्लाइट चुनने का एक और विकल्प मिलेगा।

एनडीपीएस अभियान के तहत 62 मामले दर्ज, पुराने प्रकरणों में हुईं 51 गिरफ्तारियां

संचार जगत



जयपुर। मादक पदार्थों की तस्करी एवं अवैध कारोबार के विरुद्ध जयपुर पुलिस प्रभावी कार्रवाई कर रही है। आयुक्तालय के चारों जिलों में एनडीपीएस अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थों से संबंधित 62 प्रकरण दर्ज किए गए। साथ ही पूर्व में दर्ज प्रकरणों एवं चालानशुदा मामलों में 51 गिरफ्तारियां की गईं तथा मादक पदार्थों की तलाश में 518 ठिकानों पर दबिश दी गई। इस अभियान के तहत जयपुर पूर्व जिले में 14 प्रकरण दर्ज किए गए तथा पहले से दर्ज प्रकरणों एवं चालानशुदा मामलों में 14 गिरफ्तारियां की गईं। जिले में मादक पदार्थों की तलाश में सर्वाधिक 200 ठिकानों पर दबिश दी गई। जयपुर पुलिस द्वारा नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है।

देवनानी ने गुप्ता के निधन पर जताया शोक

संचार जगत



जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता आर. के. दास गुप्ता के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। देवनानी ने कहा कि आर. के. दास गुप्ता का निधन दुखद एवं समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। सार्वजनिक जीवन एवं विधि क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान था।

लव स्टोरी ऑफ अभिमन्यु फिल्म का हुआ प्रमोशन

संचार जगत



जयपुर। तीस अक्टूबर को रिलीज हो रही हिंदी फिल्म लव स्टोरी ऑफ अभिमन्यु के प्रमोशन के सिलसिले में फिल्म के लीड रोल अभिनेता विशाल मोहन महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने फिल्म से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर फैकल्टी और स्टूडेंट्स से बातचीत की और फिल्म के बारे में जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि फिल्म उनका प्यार है। विशाल ने बताया कि यह फिल्म एक प्रेम कहानी पर आधारित है, जिसमें विशाल मोहन प्रमुख भूमिका में हैं। फिल्म में प्रगति तिवारी, अंकित भदाना, सुविंदर विक्की, मानसी रावत एवं कुलदीप सिंह रावत सहित अन्य कलाकार भी शामिल हैं। फिल्म का निर्देशन अंकित भदाना ने किया है, जबकि निर्माता संदीप तोमर हैं। विशाल मोहन ने कहा कि इस साफ सुथरी पारिवारिक फिल्म की कहानी प्रेम, भावनाओं, संघर्ष और मानवीय रिश्तों के विभिन्न पहलुओं को सामने रखती है।

नगर निगम का अतिक्रमण पर एक्शन

संचार जगत

जयपुर। शहर में अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम जयपुर की सतर्कता शाखा ने मंगलवार को व्यापक कार्रवाई की। निगम आयुक्त ओम कसेरा के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में विभिन्न इलाकों से अतिक्रमण हटाया गया। टीम ने मौके से 7 कैंटर सामान जब्त किया और अतिक्रमण करने वालों से 38 हजार रुपये कैरिंग चार्ज वसूल किया। कई इलाकों में पहुंची सतर्कता टीम उपायुक्त सतर्कता के नेतृत्व में टीम ने लालकोठी स्कीम के नकुलपथ, टोंक फाटक के बरकत नगर, मधुवन कॉलोनी किसान मार्ग, दुर्गापुरा पुलिया के नीचे, श्योपुर रोड, एनआरआई सर्किल और मालवीय नगर स्थित जूडियो के आसपास कार्रवाई की।

डीएमएफटी फण्ड को बनाएं विकास का माध्यम : सीएस

संचार जगत

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन फण्ड से प्राथमिकता क्षेत्र के कार्यों पर विशेष जोर देते हुए खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास का प्रमुख माध्यम बनाएं। उन्होंने कहा कि पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, युवाओं और महिलाओं के कौशल विकास सहित प्राथमिकता क्षेत्र के कार्यों पर फोकस करने के साथ ही कार्यों की गुणवत्ता पर पूर्णता पर ध्यान देना होगा। सचिवालय में आयोजित डिस्टिक्ट मिनरल फाउण्डेशन की राज्य स्तरीय समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि डीएमएफटी फण्ड के गुणवत्तापूर्ण और बेहतर उपयोग के लिए कलेक्टर्स स्तर पर डीएमएफटी संचालन समितियों की नियतकालीन बैठकें आयोजित करने क्षेत्र की आवश्यकताओं को चिन्हित करने और विकास परक कार्यों की स्वीकृति और प्रभावी मोनेटरिंग व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने वित विभाग को निर्देश दिए कि कार्यों की गुणवत्ता और प्राथमिकता देखते हुए राशि स्वीकृत करें और प्रभावी मोनेटरिंग तय की जाएं। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस अपर्णा अरोरा ने बताया कि डीएमएफटी से खनन प्रभावित क्षेत्रवासियों को पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, पर्यावरण विकास सहित प्राथमिकता क्षेत्र के कार्य कराने के साथ ही 30 प्रतिशत राशि से सड़क, आधारभूत संरचना आदि कार्य कराने के प्रावधान है। डीएमएफटी फण्ड से संबंधित जिलों में अब तक 12 हजार 311 करोड़ 15 लाख रुपए की राशि के कार्य स्वीकृत किये जा चुके हैं ।

ऊर्जा क्षेत्र सुधार 2.0 के तहत डिजिटल तकनीक, एआई एवं नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण पर जोर-मुख्य सचिव

संचार जगत



जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट में देशभर के विद्युत वितरण निगमों को अपने बेस्ट प्रेक्टिसेज, नवाचारों तथा धरातल के सकारात्मक अनुभवों को परस्पर साझा करने का मंच मिला है। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक आर्थिक ताकत के रूप में उभर रहा है। उस अनुरूप देश में 'ऊर्जा की मांग में भी बढ़ोतरी भी हो रही है। जयपुर में विद्युत वितरण निगमों की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के शुभारंभ सत्र में उन्होंने कहा कि विद्युत क्षेत्र सुधार 2.0 के तहत विद्युत वितरण निगम वित्तीय रूप से मजबूत बनाने की दिशा में आगे बढ़े है। अजमेर विद्युत वितरण निगम के बाद अब जयपुर डिस्कॉम का लाभ में आना निश्चय ही स्वागत योग्य है। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि विद्युत वितरण निगमों को वित्तीय रूप से सुदृढ़, तकनीकी रूप से सक्षम एवं उपभोक्ता-केंद्रित बनाना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक उपभोक्ता को निर्बाध बिजली के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण विद्युत सेवाएं उपलब्ध हो सके, इसके लिए राज्य सरकार वितरण तंत्र के सुदृढ़ीकरण की दिशा में तेजी से काम कर रही है। सम्मेलन का उद्देश्य देशभर की विद्युत वितरण कंपनियों के श्रेष्ठ अनुभवों एवं कार्यप्रणालियों को साझा कर व्यावहारिक समाधान विकसित करना है। राजस्थान को पहली बार इस राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी का अवसर मिला है।

बाल विवाह मुक्त भारत के तहत शपथ दिलाई

संचार जगत



जयपुर। समेकित बाल विकास सेवाएं, निदेशालय जयपुर मुख्यालय परिसर में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में समेकित बाल विकास सेवाओं के निदेशक वासुदेव मालावत सहित निदेशालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बाल विवाह के खिलाफ शपथ ली। इस मौके पर निदेशक मालावत ने कहा कि बाल विवाह बालक एवं बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और विकास में बड़ी बाधा है। इसे रोकने के लिए जन- जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने मुख्यालय के साथ ही सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में इस शपथ को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं एवं आमजन तक पहुंचाने के हेतु प्रयास करने निर्देश दिए।

56 कॉलोनियों को बीसलपुर का पानी मिलने की उम्मीद

संचार जगत



जयपुर। जयपुर के पृथ्वीराज नगर फेज-द्वितीय की 56 कॉलोनियों को बीसलपुर का पानी मिलने की उम्मीद है। इन कॉलोनियों में रहने वाले 35 हजार से ज्यादा लोगों को पानी की किल्लत से राहत मिल सकती है। जलदाय विभाग और बीसलपुर प्रोजेक्ट के इंजीनियर इन इलाकों में सप्लाई शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए जयसिंहपुरा, बासड़ी स्कूल, सिंवार गौशाला और कृष्णा वन विस्तार क्षेत्र में चार पानी की टंकियों से सप्लाई की जाएगी। हर टंकी की क्षमता 20 लाख लीटर है। साथ ही पूरे सिस्टम में करीब एक करोड़ लीटर अतिरिक्त पानी बढ़ाने की योजना पर भी काम चल रहा है। विभाग ने कॉलोनियों में पानी के कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। लेकिन फिलहाल हालात ये हैं कि पृथ्वीराज नगर फेज-द्वितीय की कई कॉलोनियों में लोगों को चार दिन में सिर्फ एक बार पानी मिल रहा है। ऐसे में परिवारों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पानी का अलग से इंतजाम करना पड़ता है। अब उम्मीद है कि दिवाली के बाद सप्लाई शुरू होने से लोगों को राहत मिलेगी।

फायर मॉक ड्रिल की दी ट्रेनिंग

जयपुर। होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान और जयपुर होटल एसोसिएशन के सहयोग से फतेह सिंह बाजार रेलवे स्टेशन और सिंधी कैंप बस स्टैंड के पास विवेक नगर में फायर मॉक ड्रिल की गई। इसका उद्देश्य होटल मालिक एवं होटल स्टाफ को अग्निकांड की घटनाओं को रोकने के लिए ट्रेनिंग देना था। इस अभियान में होटल में सर्विस करने वाली मातृशक्ति को भी सम्मिलित किया गया। इस अवसर पर होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान और जयपुर होटल एसोसिएशन के पदाधिकारी, कार्यकारिणी के सदस्य और बड़ी संख्या में होटल के मालिक और कर्मचारी उपस्थित रहे। मॉक ड्रिल के अंत में सभी ने फायर डिपार्टमेंट के सदस्यों को सम्मानित किया।



संपादकीय

पर्यटन के नेतृत्व में

पर्यटन निवेश के बड़े मानचित्र पर हिमाचल जो उकेरना चाहता है, उसकी लागत का अनुमान पंद्रह हजार करोड़ आंका गया है। विडंबना यह रही कि हिमाचल में पर्यटन परियोजनाओं के खाके में सियासी प्राथमिकताएं कहीं अन्यत्र चली गईं। अब हाई एंड टूरिज्म की परिभाषा में अगर नक्शा बनाने की जरूरत समझी जा रही है, तो इसे प्रदेश की समग्रता में देखना होगा। यानी हाई एंड टूरिस्ट के हिसाब से धरोहर, इवेंट, ट्राइबल, धार्मिक, साहसिक खेलों तथा प्राकृतिक पृष्ठभूमि के क्षेत्रों में वरीयता मिलनी चाहिए। हिमाचल पर्यटन के नए सर्किट धरोहर व ट्राइबल टूरिज्म को पुख्ता कर सकते हैं, जबकि तिब्बती पर्यटन की रूप रेखा में डलहौजी-धर्मशाला-कुल्लू-मनाली के सर्किट में गतिशीलता लाई जा सकती है। प्रदेश के तीन हवाई अड्डों की मौजूदगी में शिमला, मनाली और धर्मशाला में कानवेंशन टूरिज्म से कारपोरेट जगत को आकर्षित किया जा सकता है। विडंबना यह है कि धर्मशाला का प्रस्तावित कानवेंशन सेंटर पिछले एक दशक से फाइलों की धूल फांक रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में गोल्फ ग्राउंड तथा थियेटर गतिविधियों से जुड़ी अधोसंरचना को मजबूत किया जा सकता है। हिमाचल के प्रमुख मंदिरों को सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित करें, तो वहां लोककलाओं के जरिए हिमाचल की संस्कृति अपनी पैरवी करेगी। हिमाचल के विभिन्न कला संग्रहालयों में गतिविधियां बढ़ाते हुए कई वार्षिक आयोजन जोडऩे होंगे। पिछले कुछ सालों से कसौली लिट फेस्ट के कारण देश के चर्चित साहित्यकार एवं बौद्धिक समाज के जुटने से ऐसे आयोजनों की मांग बढ़ी है। अगर धर्मशाला का क्रिकेट स्टेडियम अपने आयोजनों से कई पांच सितारा होटलों का निर्माण करा सकता है, तो इसी तरह स्कीइंग, ट्रैकिंग, फिशिंग, रिवर राफ्टिंग तथा पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिताओं के आयोजन से हाई एंड टूरिस्ट को निमंत्रण भेजा जा सकता है। असम जैसे राज्य ने टी टूरिज्म की शानदार प्रस्तुति से माहौल बनाया है, तो इस अवधारणा से कांगड़ा के चायबागान भी अपनी पर्यटन क्षमता का दोहन कर सकते हैं। मसलन एचपीटीडीसी के पालमपुर स्थित टी बड होटल के पैकेज में ही टूरिज्म का निखार संभव है। करीब हजार साल के चंबा को अगर धरोहर सिटी का ताज पहनाया जाए तथा मसरूर, सुजानपुर, रामपुर, नादौन, गरली-परागपुर तथा पुराना कांगड़ा की धरोहर संपत्तियों का मूल्य सुदृढ़ किया जाए, तो हाई एंड टूरिज्म के शिलालेख प्रभावशाली होंगे। तमाम नदियों और खड्डों के किनारे रिवर फ्रंट तथा झीलों एवं जलप्रपातों के संरक्षण के साथ पर्यटन परियोजनाएं जोड़ी जाएं, तो खजियार जैसे स्थल सुकून का ऐसा पर्यटन पैदा करेंगे कि आर्थिकी की बांछें खिल जाएंगी। पर्यटन परियोजनाओं को सरकारी होटलों में जाया करने के बजाय ऐसी अधोसंरचना में लगाया जाए, जिससे डेस्टिनेशन पर्यटन को सहूलियत मिलें।

संदेहास्पद कदम वापसीः राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का विवादित फैसला

आयोग ने वर्ष 2023 के अपने 'मेडिकल शिक्षा मानक बनाए रखने संबंधी विनियमों' को अनधिसूचित करके वापस ले लिया है। इस फैसले से मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक मानकों, आधारभूत अवसंरचना और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ा दंडात्मक ढांचा काफी कमजोर पड़ गया है। यह घटनाक्रम इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि एमएसएमईआर के तहत गलत जानकारी देने वाले या फर्जी आंकड़े पेश करने वाले फैकल्टी सदस्यों और प्रशासकों पर व्यक्तिगत रूप से भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया था।

भारत में चिकित्सा शिक्षा का ढांचा सदैव देश की स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ रहा है। किसी भी राष्ट्र के नागरिकों का जीवन और स्वास्थ्य इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी मेडिकल शिक्षा प्रणाली कितनी गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी और सख्त है। हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा लिया गया एक निर्णय चिकित्सा जगत, नीति निर्माताओं और आम जनता के बीच गहरी चिंता और बहस का विषय बन गया है। आयोग ने वर्ष 2023 के अपने 'मेडिकल शिक्षा मानक बनाए रखने संबंधी विनियमों' को अनधिसूचित करके वापस ले लिया है। इस फैसले से मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक मानकों, आधारभूत अवसंरचना और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ा दंडात्मक ढांचा काफी कमजोर पड़ गया है। यह घटनाक्रम इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि एमएसएमईआर के तहत गलत जानकारी देने वाले या फर्जी आंकड़े पेश करने वाले फैकल्टी सदस्यों और प्रशासकों पर व्यक्तिगत रूप से भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया था। इस विनियम का मुख्य उद्देश्य मेडिकल शिक्षा में वर्षों से जड़ जमा चुके भ्रष्टाचार, जैसे कि फर्जी शिक्षक और फर्जी मरीज की प्रथा पर नकेल कसना था। ऐसे कड़े प्रावधानों को अचानक और पूरी तरह से समाप्त कर देने से यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या नियामक संस्था अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रही है। आयोग ने भले ही तर्क दिया हो कि यह कदम प्रक्रियात्मक दोहराव को खत्म करने के लिए उठाया गया है, लेकिन इसके व्यावहारिक परिणाम दंडात्मक तंत्र को शिथिल करने वाले साबित हो सकते हैं। चिकित्सा शिक्षा में अनुशासन और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए एक मजबूत और बहुस्तरीय दंडात्मक ढांचे की आवश्यकता हमेशा से महसूस की जाती रही है। वर्ष 2023 में जब एमएसएमईआर को लागू किया गया था, तब इसे चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में



एक ऐतिहासिक और सुधारात्मक कदम माना गया था। इसके तहत न केवल संस्थानों पर, बल्कि व्यक्तिगत रूप से उन शिक्षकों, डॉक्टरों और प्रशासनिक अधिकारियों पर भी कार्रवाई का प्रावधान था जो गलत दस्तावेज या फर्जी जानकारी जमा करते थे। इसमें दोषी पाए जाने पर पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का स्पष्ट नियम था। इसके विपरीत, 'चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, मूल्यांकन और रेटिंग विनियमों' के तहत गठित 'चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड' के पास नियम तोड़ने वाले संस्थानों पर एक करोड़ रुपये तक का भारी जुर्माना लगाने का अधिकार मौजूद है। कागजी तौर पर यह लग सकता है कि वित्तीय दंड की शक्ति अभी भी एमएआरबी के पास सुरक्षित है, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर संस्थान पर जुर्माना लगाने और दोषी व्यक्ति पर जुर्माना लगाने में बहुत बड़ा अंतर होता है। जब तक व्यक्तिगत जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक संस्थानों के भीतर बैठा भ्रष्ट तंत्र अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। देश के तमाम मेडिकल कॉलेजों में 'घोस्ट फैकल्टी' यानी कागजी शिक्षकों और 'घोस्ट पेशेंट्स' यानी अस्पताल में केवल निरीक्षण के समय दिखाए जाने वाले फर्जी मरीजों की समस्या बेहद गंभीर और पुरानी रही है। कई निजी और गैर-जिम्मेदार संस्थान निरीक्षण के समय केवल कागजों पर डॉक्टरों की भर्ती दिखा देते हैं, जो वास्तव में वहां पढ़ाते ही नहीं हैं। इसी प्रकार, अस्पतालों में बिस्तर भरने और आवश्यक मानकों को पूरा करने के लिए नकली मरीजों को दाखिला दिखा दिया जाता है। एमएसएमईआर के कड़े नियमों ने इस अनैतिक खेल पर सीधी चोट की थी। शिक्षकों और प्रशासकों को यह डर था कि गलत जानकारी देने पर उनका व्यक्तिगत करियर और जमा पूंजी संकट में पड़ सकती है। इस डर ने प्रशासकों को ईमानदार बने रहने और गलत रास्ते पर न चलने की प्रेरणा दी। अब जब इस कड़े विनियम को पूरी तरह वापस ले लिया गया है, तो यह डर काफी हद तक समाप्त हो गया है। आयोग ने अपने इस फैसले का औचित्य साबित करते हुए कहा है कि एमएसएमईआर ने स्नातक और स्नातकोत्तर बोर्डों को संस्थानों का अलग से मूल्यांकन करने का अधिकार देकर एक समानांतर व्यवस्था खड़ी कर दी थी। आयोग का तर्क है कि इससे एमएआरबी के मूल अधिकार क्षेत्र में दखलअंदाजी हो रही थी। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अधिकार क्षेत्र का कोई टकराव था, तो विनियम में आवश्यक संशोधन किए जा सकते थे, न कि पूरे दंडात्मक ढांचे को ही निरस्त कर दिया जाता। एक ओर जहां स्नातक स्तर पर दंडात्मक तंत्र ढीला हुआ है, वहीं स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम अभी भी लागू हैं, जिनमें व्यक्तिगत फैकल्टी सदस्यों पर जुर्माना लगाने के नियम शामिल हैं। इससे एक अजीबोगरीब विरोधाभास पैदा हो गया है। स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरों के लिए अलग-अलग दंडात्मक मापदंड होना न केवल भ्रम पैदा करता है बल्कि प्रशासनिक विसंगतियों को भी जन्म देता है। इसके अतिरिक्त, दंड देने की प्रक्रियाओं और उनकी अपील से जुड़ी समय-सीमाओं को लेकर भी भारी कानूनी विरोधाभास सामने आ रहे हैं। एमएआरबी के नियमों में किसी कार्रवाई के खिलाफ अपील करने की समय-सीमा पंद्रह दिन निर्धारित की गई है, जबकि एनएमसी अधिनियम के तहत अपील दायर करने की अवधि साठ दिन दी गई है। यह समय-सीमा का टकराव भविष्य में कई कानूनी विवादों को जन्म दे सकता है। दोषी संस्थान और व्यक्ति इस कानूनी ढील का फायदा उठाकर अदालतों से स्थगन आदेश प्राप्त कर लेंगे, जिससे दंडात्मक कार्रवाई महीनों और सालों तक टल जाएगी। जब नियमावलियों के बीच ही तालमेल नहीं होगा, तो नियम तोड़ने वालों को बचना बेहद आसान हो जाएगा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की कार्यप्रणाली और उसकी पारदर्शिता पर पहले भी कई बार गंभीर सवाल उठ चुके हैं। एक सार्वजनिक सूचना अधिकार (आरटीआई) याचिका के माध्यम से केंद्रीय सूचना आयोग के सामने जो तथ्य उजागर हुए, वे बेहद हैरान करने वाले हैं। आरटीआई के तहत दी गई जानकारी में यह बात सामने आई कि एमएआरबी ने वर्ष 2024 तक देश के अधिकांश मेडिकल कॉलेजों का न तो कोई औपचारिक मूल्यांकन किया था और न ही उन्हें कोई आधिकारिक रेटिंग दी थी।

सत्ता से अधिक व्यवस्था परिवर्तन जरूरी

देश की वर्तमान चुनौतियों से निपटने के लिए समाज, सरकार, विपक्ष और उद्योगपति नानाजी के व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा ले सकते हैं। जेन-जी के आंदोलन और सड़कों पर हो रहे विरोध प्रदर्शन की सर्वाधिक चर्चा है। नानाजी ने जेपी के साथ मिलकर आपातकाल के खिलाफ युवाओं के सबसे बड़े आंदोलन से सत्ता परिवर्तन को सफल बनाया था। जनता पार्टी की सरकार में उन्होंने मंत्री पद लेने से इनकार करने के बाद सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था। चित्रकूट में दीनदयाल शोध संस्थान और ग्रामोदय विश्वविद्यालय के माध्यम से उन्होंने गांवों के सशक्तीकरण से विकसित भारत का रोडमैप बनाया था। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित 80 गांवों को मुकदमेबाजी से मुक्त देखकर पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम बहुत प्रभावित हुए थे। उनके अनुसार पिछली सदी के आठवें दशक के बाद मानवीय स्पर्श से जुड़ी सामाजिक व्यवस्था कमजोर होने के साथ अदालतों में मुकदमेबाजी बढ़ गई। वर्ष 2006 में भारत की आबादी लगभग 117 करोड़ थी और अदालतों में 2.87 करोड़ मुकदमे लंबित थे। उसके 20 साल बाद आबादी लगभग 25 प्रतिशत बढ़ी, लेकिन मुकदमों की संख्या 5.84 करोड़ यानी दोगुनी से ज्यादा हो गई है। मुकदमों की बढ़ती संख्या से तीन निष्कर्ष निकाले जा सकते



हैं। पहला, सरकारी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में विफल हैं, जिसकी वजह से न्यायपालिका की भूमिका बढ़ती जा रही है। दूसरा, पुलिस सुधार नहीं होने से गिरफ्तारी और जमानत से जुड़े मुकदमों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तीसरा, संविधान लागू होने के 76 साल बाद भी न्यायिक व्यवस्था में जरूरी सुधार नहीं हुए। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल के अनुसार मुकदमेबाजी के बढ़ते बोझ से उत्पादकता घटने के साथ विदेशी निवेश भी प्रभावित होता है। केंद्र सरकार ने जनविश्वास कानून के माध्यम से अनेक अपराधों को अनापराधिक बनाने के साथ तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू किया है। डिजिटल दुनिया में संवाद, संचार, भुगतान, व्यापार सभी कुछ तेजी से हो रहा है, लेकिन हमारी न्यायिक व्यवस्था अभी भी कछुए की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। सड़कों पर बढ़ रही अराजकता और अदालतों में हावी हो रहे भीड़तंत्र को रोकने के लिए पुलिस और न्यायिक सुधार जरूरी हैं। चीन से बढ़ते आयात और अमेरिका के दबाव से स्वदेशी अर्थव्यवस्था पर बेहद दबाव है। गांवों को विवादों से मुक्त कराने के साथ नानाजी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और कुटीर उद्योगों के विकास से आत्मनिर्भरता बढ़ाने के प्रकल्पों को सशक्त किया था। इसके लिए उन्होंने स्वदेशी पूंजी, ग्रामीण श्रम, आधुनिक विज्ञान और जनसहयोग को परस्पर जोड़ने का यत्न किया था। चार दशक पहले उन्होंने उद्योगपतियों को बुंदेलखंड के चित्रकूट जैसे पिछड़े क्षेत्र में निवेश और आधुनिक तकनीक लाने के लिए प्रेरित किया। नानाजी ने देश के पहले ग्रामीण विश्वविद्यालय का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा। विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से जुड़कर उन्होंने भूमिहीनों और वंचित वर्ग का सशक्तीकरण किया। जयप्रकाश नारायण और उनकी पत्नी प्रभावती के नाम से गोंडा में उन्होंने जयप्रभा ग्राम का नामकरण किया। उनका बचपन भुखमरी और संघर्षों में बीता, पर वे हिंसक और माओवादी नहीं बने। जन-आंदोलनों से चुनावी राजनीति और सत्ता परिवर्तन के बारे में नानाजी की सफलता से सभी दलों के नेता प्रेरणा ले सकते हैं। वर्ष 2017 में नानाजी की स्मृति में जारी डाक टिकट के अनुसार समाज में परस्पर सहयोग से ही ग्रामोदय हो सकता है। वंचित वर्ग के लिए सब्सिडी और कल्याणकारी योजनाएं जरूरी हैं, लेकिन चुनावी लाभ के लिए रेवड़ियां और स्वावलंबन के बजाय रीलबाजी की बढ़ती संस्कृति विकसित भारत की राह में बड़ा रोड़ा है। भारत की शासन व्यवस्था में विदेशी ताकतों के हस्तक्षेप को कम करने के लिए एफसीआरए कानून को सख्त बनाया जा रहा है, लेकिन विदेशी सोशल मीडिया कंपनियों के माध्यम से चुनावी राजनीति और जन-आंदोलनों को संचालित करने से रोकने के लिए कानूनों को लागू नहीं किया जा रहा है। सोशल मीडिया और आनलाइन गेमिंग से बच्चों की सुरक्षा और ई-कामर्स के फास्टफूड के दौर में उनका खानपान स्वस्थ रखना परिवारों के लिए बड़ी चुनौती है, जिस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। यूपीआई, ओटीटी, ई-कॉमर्स, सीसीटीवी, स्पेस सैटेलाइट जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विदेशी कंपनियों का वर्चस्व चिंताजनक है।

2047 के भारत के लिए नए विमर्श की तलाश में भाजपा

भाजपा 2047 तक सत्ता में बने रहना चाहती है। मतलब यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि 2047 की 15 अगस्त को जो भी प्रधानमंत्री लालकिले की प्राचीर से देश को संबोधित करे, वो भारतीय जनता पार्टी का नेता हो। यानि भाजपा की नजर उन सब नेताओं पर है, जो वर्तमान में चालीस से पचास साल की आयु वर्ग में हैं। इस बात का यह भी अर्थ निकाला जा सकता है कि आनेवाले बीस सालों में भाजपा में ऐसे कार्यकर्ताओं की आवश्यकता रहेगी, जो नेहरू की विफलताओं से आगे सोचें और विकसित भारत के अलग अलग आयामों पर अपना स्वतंत्र विचार रखते हों। यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि अब भाजपा का समर्थक वर्ग भी नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस शासन के दुष्परिणामों के आरोपों को और नहीं सुनना चाहता। वो अब किसी नए विमर्श की तलाश में है। उन्हें वही भाजपा नेता समझ में आ रहा है जो नए विमर्श और कार्य के साथ राजनीति कर रहा है। प्रश्न यह भी उठता है कि क्या उस समय तक भारत की राजनीति बिल्कुल बदल



जाएगी, जिसमें विपक्षी दलों की भूमिका उपस्थिति मात्र रहेगी। क्या यह भी संभव होगा कि विपक्षी दलों से चुनकर आने वाले सांसद सरकार में मंत्री की भूमिका निभा रहे होंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिज्ञों की जगह पूर्व नौकरशाहों को अपनी कैबिनेट में जगह दी है, उससे यह लगता है कि वे ही शशि थरूर जैसे नेता को मंत्री बनाकर इस नई राजनीति की शुरुआत भी कर सकते हैं। राजनीति के इस परिवर्तन को स्वीकार भी कर लिया जाएगा, क्योंकि मोदी चौंकाने वाली राजनीति करने में सिद्धहस्त हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि इन सबके बीच कांग्रेस क्या करेगी। क्या कांग्रेस बची भी रहेगी या राहुल गांधी के अहंकारी और अक्खड़ स्वभाव के कारण कांग्रेस में शेष रहे जन नेता अपने लिए दूसरा विकल्प ढूँढ लेंगे। वैसे क्षेत्रीय दलों का पराभव कांग्रेस की वापसी के सुनहरे अवसर प्रदान करता है, पर कांग्रेस संगठन में लिए जाने वाले एकाकी और अदूरदर्शिता पूर्ण निर्णय इन अवसरों में उपजे मौकों का साफ़ खोते नजर आ रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में यह माना जा रहा है कि राहुल गांधी को पर्दे के पीछे रहकर ऐसे नेताओं के हाथों में कांग्रेस संगठन की बागडोर दे देनी चाहिए, जिन पर कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता का भी भरोसा हो। कांग्रेस ताकतवर होगी तो गांधी परिवार की भी ताकत बढ़ेगी अभी तो राहुल गांधी की ताक़त बढ़ाने की कीमत कांग्रेस पार्टी ही चुका रही है। अगले साल होने वाले चुनावों में गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड से ही कांग्रेस को उम्मीद है। ध्यान रहे कि इन तीनों राज्यों में सिर्फ 9 लोकसभा सीट हैं। जबकि 80 लोकसभा वाले उत्तर प्रदेश और 13 लोकसभा वाले पंजाब में तो वो सत्ता से दूर बहुत दूर हैं।

महंगी दवाएं बढ़ा रहीं इलाज का बोझ

सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष माना है कि अस्पताल नियमित रूप से दवाओं और अन्य उत्पादों के लिए अतिरिक्त कीमत वसूल करते हैं। इससे दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण की व्यवस्था को बेहतर बनाने की थोड़ी उम्मीद जरूर जगी है। हालांकि एक व्यापक प्रभावी व्यवस्था बनाना आसान नहीं होगा। कनाडा या यूरोपीय संघ जैसे पश्चिमी देशों में दवाओं के मूल्य-निर्धारण में मुनाफा मार्जिन और विनिर्माताओं की लागत को लेकर जो सीमाएं लगाई जाती हैं उनके पीछे वहां लगभग सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था है। इन देशों में बड़े पैमाने पर दवाओं की सरकारी खरीद की जाती है जो एक तरह से एकाधिकार वाली खरीद व्यवस्था भी है। दूसरी तरफ, भारत की स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका लगातार बढ़ रही है। ऐसे में दवाओं की कीमतों पर तय सीमा का पालन सुनिश्चित करना मुश्किल है। यह काफी हद तक अस्पतालों, क्लीनिकों और दवा विक्रेताओं के संयम और स्वेच्छा पर निर्भर करता है। सरकार को इसमें हस्तक्षेप के उपायों पर विचार करना चाहिए। यह मामला एक जनहित याचिका के बाद सामने आया है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय से जेनेरिक दवाओं, अन्य औषधियों और चिकित्सा उपकरणों की कीमतों को नियंत्रित करने की मांग की गई है। सरकार के हलफनामे में कहा गया है कि अस्पताल कई दवाओं पर 170 से 700 फीसदी तक, जबकि चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाली उपभोग्य वस्तुओं पर 100 से 1,000 फीसदी तक अतिरिक्त मूल्य वसूलते हैं। अदालत खुद जीवनरक्षक दवाओं विशेषकर कैंसर की दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य में की जाने वाली भारी बढ़ोतरी को 'डकैती' कह चुकी है। सरकार ने माना है कि मरीज और अस्पताल के बीच जानकारी की असमानता ही ऐसी अनुचित कीमत वसूली का प्रमुख कारण है। इस समस्या का एक हिस्सा सरकार की दवा मूल्य नियंत्रण व्यवस्था में भी निहित है। दवाओं को दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में 'अनुसूचित' दवाएं आती हैं। ये आवश्यक दवाएं हैं जिनका मूल्य सरकार तय करती है। इनमें इंसुलिन, कुछ एंटीबायोटिक्स, अवसादरोधी दवाएं और टीबी की दवाएं शामिल हैं। दूसरी श्रेणी 'गैर-अनुसूचित' दवाओं की है जिनकी कीमतें तय करने की छूट विनिर्माताओं को होती है। 80 फीसदी से अधिक दवाएं गैर-अनुसूचित श्रेणी में आती हैं और इनमें कैंसर की दवाएं भी शामिल हैं। 9 नवंबर, 2026 से प्रभावी व्यवस्था के तहत राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने कैंसर की 137 दवाओं पर व्यापारिक मार्जिन अधिकतम खुदरा मूल्य के 30 फीसदी तक सीमित कर दिया है। इस हस्तक्षेप से जीवनरक्षक कैंसर दवाओं के मूल्य में 70 फीसदी तक की कमी आने की उम्मीद है। संसद की एक स्थायी समिति ने निजी अस्पतालों के शुल्क को मानकीकृत करने, कमरों का किराया तीन सितारा होटलों की दरों तक सीमित करने और चिकित्सा प्रक्रियाओं की लागत का अनिवार्य खुलासा सुनिश्चित करने की सिफारिश की है। प्रश्न यह है कि ऐसे सरकारी निर्देशों को कितने प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है। कीमतों पर नियंत्रण के उलटे परिणाम सामने आने का भी खतरा रहता है। कीमतों पर नियंत्रण के कारण जब कई दवाओं का उत्पादन घरेलू निर्माताओं के लिए लाभकारी नहीं रह गया तो बड़ी संख्या में थोक दवाओं के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले प्रमुख रासायनिक घटकों की आपूर्ति चीन से की जाने लगी। भारत दवाओं के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले सक्रिय औषधीय घटकों (एपीआई) का लगभग दो-तिहाई हिस्सा चीन से आयात करता है। कोविड लॉकडाउन के दौरान इस निर्भरता का असर गंभीर रूप से महसूस किया गया। सरकार को दवा उत्पादकों और खुदरा विक्रेताओं की मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाने तथा मरीजों के हितों की रक्षा करने के बीच संतुलन बनाना होगा। मरीजों के अधिकारों और दवाओं की मूल्य निर्धारण नीतियों के बारे में व्यापक स्तर पर बहुभाषी जागरूकता अभियान चलाने से जानकारी की असमानता को दूर करने में काफी मदद मिल सकती है।

लघु कथा

मेरे हिस्से का घर-परिवार

देख संगीता, मैं बाज़ार से यह सलेक्स ले आई हूँ। तुम कल कह रही थी न कि तुम्हारी पीली वाली सलेक्स खराब हो गई है? इसलिए यह ले आई। संगीता के चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं आई। उसने पूछा, कितने की है यह सलेक्स?

सासू माँ बोलीं, छः सौ पचास रुपये की।

संगीता खीझकर बोली, इतनी महँगी सलेक्स लाने की क्या ज़रूरत थी? मुझे नहीं चाहिए। कल वापस कर आइए।

सासू माँ का चेहरा उतर गया। ठीक है,' वे धीमे स्वर में बोलीं और उदास मन से अपने कमरे में चली गईं।

अभय यह सब देख रहा था। माँ के जाते ही बोला, तुमने ठीक नहीं किया। सलेक्स रख लेती तो क्या हो जाता! अगर दुकान ने कल वापस न ली तो? माँ फिर बाजार जाएँगी, परेशान होंगी।

संगीता मुस्कुराई, आप देखते जाइए... वे कल बाज़ार नहीं जाएँगी।

अभय कुछ समझ पाता, इससे पहले ही सासू माँ वापस कमरे में आईं। हाथ में वही सलेक्स थी। बोलीं, बहू, कपड़ा बहुत अच्छा है, तुम इसे रख ही लो।

संगीता ने कहा, ठीक है, रख लेती हूँ... लेकिन आगे से मत लाइएगा।

इतना सुनते ही सासू माँ बच्चों की तरह खिल उठीं, फिर बोलीं, इस रिमझिम को देखो, मेरी एक नहीं सुनती! कल झाड़ू लगाते हुए कोनों में कूड़ा छोड़ दिया था। तुम इसे समझा देना– मेरी बात माने, वरना काम से निकाल दूँगी।' इतना कहकर वे रिमझिम को आवाज़ देती बाहर चली गईं।

संगीता रसोई की ओर बढ़ने लगी तो अभय बोला, जब आखिर में सलेक्स रखनी ही थी तो पहले क्यों नहीं रख ली?

संगीता हँस दी, पहले रख लेती तो कल कुछ और नया ले आतीं।

अभय बोला, सच कहूँ, माँ के साथ निभाना आसान नहीं। तभी तो मेरा कोई भाई-बहन उन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहता।

संगीता ने पलटकर पूछा, पर माँ को साथ नहीं रखेंगे तो बच्चों को दादी का प्यार कौन देगा? और वे रहेंगी कहाँ?

अभय ने कहा, फिर तुम दोनों सारा दिन नोकझोंक क्यों करती रहती हो? तुम माँ के हर काम में मीन-मेख निकालती हो।

संगीता बोली, देखिए, बच्चे और बुजुर्ग एक जैसे होते हैं। जितनी बात मानो, माँगें उतनी बढ़ती जाएँ। कई बार रोक लगानी पड़ती है। ...लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनके साथ न रहा जाए। यही तो मेरे हिस्से का घर-परिवार है।

अभय बोला, माँ हर किसी में कमी निकालती रहती हैं। रिमझिम तो उनसे बहुत परेशान है।

इंडिया गठबंधन ने रामलीला मैदान में रैली की तैयारियां तेज की

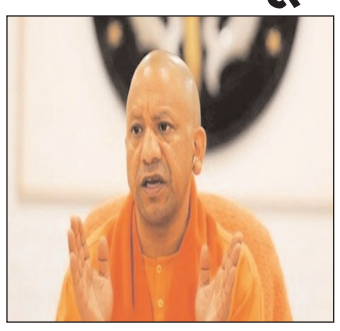
संचार जगत



नई दिल्ली। विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने कथित वोट चोरी, एसआईआर में कथित अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रस्तावित रैली की तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस और गठबंधन के अन्य सहयोगी दल इस रैली को सफल बनाने की तैयारियों में जुटे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को रामलीला मैदान का दौरा कर रैली की तैयारियों का जायजा लेने वाले हैं। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल भी प्रस्तावित रैली से पहले रामलीला मैदान पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि इंडिया ब्लॉक की रैली में भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है। उन्होंने दावा किया कि देशभर से करीब 10 लाख लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जंतर-मंतर को विरोध-प्रदर्शनों के लिए खुला रखने की अपनी मांग जारी रखेगी। हालांकि, प्रस्तावित रैली में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना को देखते हुए रामलीला मैदान को अधिक उपयुक्त स्थान बताया। इस बीच, चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने रैली को दिवाली के बाद आयोजित करने की अपनी मांग दोहराई है। राहुल गांधी द्वारा रैली की तारीख बदलने की मांग खारिज किए जाने के एक दिन बाद सीटीआई के चेयरमैन बृजेश गोयल ने कांग्रेस नेता को विस्तृत पत्र लिखा। संगठन ने पत्र की एक प्रति कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी भेजी है।

योगी कैबिनेट ने 22 प्रस्तावों को दी मंजूरी

संचार जगत



लखनऊ । उत्तर प्रदेश में पशुपालन को रोजगार और किसानों की आय बढ़ाने का जरिया बनाने से लेकर शिक्षा क्षेत्र के कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने तक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में पेश किए गए सभी 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें गाय पालन पर 50 फीसदी तक सब्सिडी, पशुओं के बीमा में सरकारी सहायता, नावों और स्टीमर के संचालन के लिए नियमावली, कंपनियों के विलय-विभाजन की प्रक्रिया आसान बनाने और मैनपुरी में सैनिक स्कूल के विस्तार के लिए जमीन उपलब्ध कराने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं। सरकार ने पशुधन क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने, निवेश को प्रोत्साहित करने, जल परिवहन को व्यवस्थित करने और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुरक्षा देने पर विशेष जोर दिया। कैबिनेट ने शिक्षा क्षेत्र से जुड़े शिक्षकों और कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। बैठक में उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के लिए आवास निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

चुनाव की तारीख घोषित होते ही हार जाएगी भाजपा-अखिलेश

संचार जगत



लखनऊ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले दल-बदल और सियासी समीकरणों को साधने की कवायद तेज हो गई है। बरेली की आंवला लोकसभा सीट से भाजपा के पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप अपनी बेटी कीर्ति कश्यप और समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। बहुजन समाज पार्टी के आबिद अली ने भी सपा की सदस्यता ग्रहण की। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सभी को पार्टी में शामिल कराया और इसे सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूती देने वाला कदम बताया। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि उनके आने से सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूती मिलेगी। पार्टी उन्हें पूरा राजनीतिक सम्मान और उचित स्थान देने में कोई कमी नहीं रखेगी। अखिलेश ने दावा किया कि जिस दिन चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, उसी दिन भाजपा की हार तय हो जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि हार के डर से भाजपा बेईमानी और चुनावी हेराफेरी का सहारा ले रही है। उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, मतदाता सूची में नाम काटे जाने और मतदान व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए। अखिलेश ने कहा कि आने वाला चुनाव केवल सत्ता हासिल करने की लड़ाई नहीं, बल्कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा को पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग की एकजुटता से डर लग रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की पेरोल बढ़ाने से किया इनकार

संचार जगत



नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम की पेरोल बढ़ाने से इनकार कर दिया। इस कारण पिछले 20 दिन से बाहर आसाराम को दोबारा जेल में लौटना पड़ेगा। आसाराम पिछले 20 दिन से पेरोल पर जेल से बाहर है। इसके पहले, आसाराम ने मेडिकल आधार पर पेरोल बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। याचिका में आसाराम के वकील ने कहा था कि वह उज्जैन के अस्पताल में भर्ती हैं। इसलिए मेडिकल आधार पर पेरोल को बढ़ाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पेरोल बढ़ाने से इनकार कर दिया। साथ ही राजस्थान सरकार को आसाराम की सेहत का ध्यान रखने का निर्देश दिया। इससे पहले, राजस्थान हाईकोर्ट ने सजायाफ्ता आसाराम को 3 अगस्त को 20 दिन की पैरोल दी थी। 2018 में, जोधपुर की एक विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आसाराम को एक नाबालिग के साथ बलात्कार और यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

रूस-यूक्रेन की सहमति से ओलेश्की में सीज फायर

संचार जगत



कीव। रूस और यूक्रेन ने ओलेश्की शहर में मानवीय सहायता कार्य शुरू करने के लिए एक क्षेत्रीय संघर्ष विराम लागू कर दिया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख किरिलो बुडानोव ने सोशल मीडिया पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। हालांकि, अन्य जगहों पर, जिसमें यूक्रेन की राजधानी कीव भी शामिल है, हमले अभी भी जारी हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी संसद के आयुक्त, दमित्रो लुबिनेट्ज मौके पर पहुंच गए हैं और वे इस पूरी प्रक्रिया के समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। हम लगातार उनके संपर्क में हैं। बुडानोव ने इसे मिशन की कामयाबी को आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण बताया।

चक्रवात अर्नब को लेकर पश्चिम बंगाल में अलर्ट



संचार जगत

कोलकाता । चक्रवात अर्नब के अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने और आज आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की आशंका के बीच पश्चिम बंगाल में भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कोलकाता स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के कई तटीय जिलों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश, गरज के साथ बौछारें और तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने समुद्र में खराब परिस्थितियों की आशंका को देखते हुए मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी है। चक्रवात के प्रभाव से समुद्र की स्थिति बिगड़ने और ऊंची लहरें उठने की संभावना है। चेतावनी के अनुसार गुरुवार तक मछली पकड़ने की गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। आज मौसम और खराब होने की आशंका है। दक्षिण 24 परगना, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर और झाड़ग्राम में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। इन चार जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।

व्हाइट हाउस ने भारत-अमेरिका ट्रेड डील बातचीत को बताया सकारात्मक



संचार जगत

नई दिल्ली। भारत-अमेरिका ट्रेड डील को व्हाइट हाउस ने सकारात्मक करार दिया है। वहीं, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि समझौते को लेकर ज्यादातर मुद्दों पर बातचीत पूरी हो चुकी है और अब उसके अंतिम प्रारूप को बेहतर बनाने पर काम किया जा रहा है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता मैथ्यू मिडलटन ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन भारत के अधिकारियों के साथ सकारात्मक बातचीत कर रहा है, ताकि ऐसा ऐतिहासिक व्यापार समझौता सुनिश्चित किया जा सके जो अमेरिका और अमेरिकी हितों को प्राथमिकता दे। यह बयान ऐसे समय आया है, जब गोयल ने नीदरलैंड के हेग में आयोजित भारत-नीदरलैंड बिजनेस फोरम में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता का बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका है। गोयल जर्मनी और नीदरलैंड की यात्रा पर गए भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने पिछले साढ़े चार वर्षों में नौ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं।

शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान में तेजी लाने के दिए निर्देश

संचार जगत



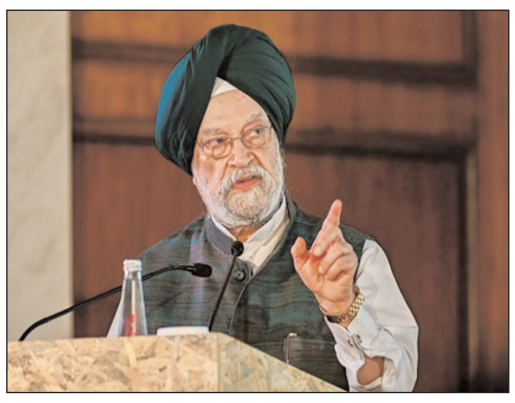
जयपुर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने दीपावली के त्योहारी सीजन को देखते हुए प्रदेश में शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। खाद्य पदार्थों में मिलावट कर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कार्रवाई पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ हो तथा किसी भी प्रकार के दबाव या दुर्भावना में कार्रवाई नहीं की जाए। स्वास्थ्य भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं और विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की।

मध्यप्रदेश कैबिनेट ने 4 सिंचाई परियोजनाओं को दी मंजूरी

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में किसानों, सामाजिक कल्याण, शिक्षा, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। बैठक के बाद एमएसएमई मंत्री चेतन्य कश्यप ने बताया कि नर्मदा घाटी विकास की चार सिंचाई परियोजनाओं की निरंतरता के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं पर कुल 3,378 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये परियोजनाएं छिंदवाड़ा, मुरैना, सागर और सिवनी से संबंधित हैं। इसके साथ ही वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने की तैयारियों और इसके विभिन्न आयामों पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण भी दिया गया।

रूस से तेल आयात कम करने का दबाव नहीं : हरदीप पुरी

संचार जगत



नई दिल्ली। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि भारत कच्चे तेल के लिए अपने हित को केंद्र में रखकर फैसले ले रहा है और फिलहाल रूसी तेल आयात कम करने के लिए अमेरिका को कई दबाव नहीं है। एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मध्य-पूर्व से कच्चे तेल की आपूर्ति में तेज वृद्धि हुई है। बड़ी संख्या में कार्गो क्षेत्र से बाहर निकल पा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि यूक्रेन युद्ध से पहले भारत केवल अपना 0.2 प्रतिशत ही कच्चा तेल रूस से आयात करता था, लेकिन रूसी कच्चे तेल पर डिस्काउंट के चलते आयात में तेज वृद्धि हुई। सितंबर में भारत का मध्य-पूर्व से कच्चे तेल का आयात काफी बढ़ गया है और यह युद्ध-पूर्व के स्तर पर वापस आ गया है। वहीं, चीन से मिल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच, रिफाइनरियों ने रूसी तेल की खरीद कम कर दी है। रूसी तेल का आयात इसलिए कम हुआ है क्योंकि रिफाइनरियां अब खाड़ी देशों से मिलने वाला वह तेल ज्यादा खरीद रही हैं, जो छूट पर उपलब्ध है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आखिरकार, हर फैसला अपने ही फायदे को ध्यान में रखकर लिया जाता है।

दिल्ली की हवा बिगड़ने से पहले ही प्रशासन अलर्ट

संचार जगत



नई दिल्ली। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए ग्रेप -1 लागू कर दिया गया है और अब सड़कों पर एंटी स्मॉग गन से पानी का छिड़काव शुरू हो गया है। मध्य दिल्ली में मशीनों के जरिए पानी की बारीक बूंदें हवा में छोड़ी जा रही हैं, ताकि सड़कों पर उड़ने वाली धूल को कम किया जा सके। सर्दियों की शुरुआत के साथ दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने की आशंका रहती है। ऐसे में प्रशासन ने समय रहते कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। ग्रेप-1 के तहत सड़कों की नियमित सफाई, धूल पर नियंत्रण और निर्माण स्थलों पर प्रदूषण रोकने के नियमों के पालन पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर निगरानी भी रखी जाएगी। हालांकि, एंटी स्मॉग गन से सिर्फ धूल कम करने में मदद मिलती है। वाहनों के धुएं और प्रदूषण के दूसरे स्रोतों पर नियंत्रण के लिए भी सख्त कदम उठाना जरूरी है।

पैसे देकर प्रोपेगेंडा चलाया गया: गडकरी



नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि करीब 3 महीने पहले ई 20 फ्यूल का काफी विरोध हुआ था, लेकिन अब यह विरोध खत्म हो गया है। उन्होंने इसे पैसे देकर चलाया गया अभियान बताया। गडकरी का ये बयान केंद्र सरकार के 100प्रतिशत एथेनॉल-ब्लेंडेड फ्यूल के इस्तेमाल को मंजूरी देने के एक दिन बाद आया है। दरअसल, भारत में 20प्रतिशत एथेनॉल और 80प्रतिशत पेट्रोल के इस मिश्रण का विरोध हो रहा था। दावा किया गया था कि 2023 से पहले बनी पेट्रोल गाड़ियों के मालिक परेशान हैं। इस फ्यूल से गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है, मेंटेनेंस का खर्च बढ़ गया है और इंजन के पार्ट्स जल्दी खराब हो रहे हैं।

जबरन वसूली पर ऋणदाताओं को शिंदे की चेतावनी

संचार जगत



मुंबई। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों, निजी साहूकारों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और बैंकों को सूखा प्रभावित किसानों से ऋण चुकाने के लिए दबाव डालने के खिलाफ कड़ी चेतावनी जारी की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकार मानसिक उत्पीड़न या जबरन वसूली को बर्दाश्त नहीं करेगी, जिससे परेशान किसान चरम कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रशासन किसान समुदाय के साथ मजबूती से खड़ा है। उपमुख्यमंत्री ने राज्य के जीरो टोलरेंस के रुख पर जोर दिया। उन्होंने नांदेड़ में हाल ही में हुई आक्रामक ऋण वसूली की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि चाहे वह सूक्ष्म वित्त फर्म हो, वित्त कंपनी हो, बैंक हो या निजी साहूकार, किसान को परेशान करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

तमिलनाडु की जेल में कैदियों के फरार होने से हड़कंप मचा

संचार जगत

थेनी। तमिलनाडु की जेल में कैदियों के फरार होने से हड़कंप मच गया है। थेनी जिले की सब-जेल से 17 कैदी जेल कर्मचारियों पर हमला कर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस महकमे में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस ने फरार कैदियों की तलाश के लिए 17 विशेष टीमें बनाई हैं, जिनमें से चार कैदियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक कैदी की तबीयत खराब होने और उसे दौरे पड़ने की सूचना दी गई। जब जेल कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी सेल का दरवाजा खोलकर अंदर पहुंचे, तो कैदियों ने अचानक उन पर हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। इस हमले में तीन पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। एक पुलिसकर्मी के सिर में चोट आने के बाद उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद आसपास के इलाकों में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पड़ोसी डिंडीगुल जिले में 16 चेकपोस्ट बनाए गए हैं। बस स्टैंड, सड़कों और तमिलनाडु-केरल सीमा पर वाहनों की जांच की जा रही है। मदुरै, डिंडीगुल और केरल के इडुक्की जिले की पुलिस को भी अलर्ट किया गया है। तमिलनाडु में कैदियों के फरार होने की यह घटना 1995 के बाद की बड़ी घटनाओं में शामिल मानी जा रही है। उस समय वेल्लोर के विशेष डिटेंशन कैंप से लिट्टे के 43 संदिग्ध सुरंग बनाकर फरार हो गए थे।

वडोदरा में करोड़ों की अवैध शराब पकड़ी

संचार जगत



वडोदरा। गुजरात के ड्राई स्टेट में करोड़ों की अवैध शराब पकड़ी गई है। वडोदरा पुलिस ने एक गोदाम पर छापा मारकर एक करोड़ 24 लाख रुपये से ज्यादा कीमत की विदेशी शराब बरामद की। यहां शराब की एक हजार 490 पेटियां मिलीं, जिनमें 66 हजार 432 बोतलें थीं। इस कार्रवाई में राजस्थान के चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें जालोर के मनोहरलाल बिश्नोई, सांचोर के प्रकाश बिश्नोई, चितलवाना के दिनेशकुमार बिश्नोई और बाड़मेर के सेड़वा निवासी प्रवीणकुमार बिश्नोई शामिल हैं। पुलिस ने शराब के साथ करीब 4 लाख रुपये की कार और सात मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। जब्त माल की कीमत एक करोड़ 28 लाख रुपये से ज्यादा बताई गई है। शराब हरियाणा और महाराष्ट्र से मंगाकर वडोदरा और आसपास के इलाकों में सप्लाई की जानी थी। पुलिस ने नेटवर्क से जुड़े तीन अन्य लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है, जो छापेमारी के दौरान मौके पर नहीं मिले। अब पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है।

पांच राज्यों में चुनाव से पहले अधिकारियों के तबादले का आदेश

संचार जगत



नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने 2027 की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत पांच राज्यों में सरकारी अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के तबादले को लेकर निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया से सीधे जुड़े अधिकारियों की तैनाती उनके गृह जिलों या उन स्थानों पर नहीं होनी चाहिए, जहां वे लंबे समय से कार्यरत हैं। ईसीआई ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में पत्र भेजा। आयोग ने अपने तबादला संबंधी नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है, ताकि चुनाव के दौरान निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके। चुनाव आयोग ने कहा कि तबादले की नीति के दायरे में मंडलायुक्त, नगर आयुक्त, निषेध एवं आबकारी विभाग के अधिकारी और परिवहन विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे। आयोग ने स्पष्ट किया कि यह नियम उन पुलिस अधिकारियों पर लागू होंगे, जो चुनाव के दौरान जिलों में सुरक्षा व्यवस्था या पुलिस बलों की तैनाती के लिए जिम्मेदार होते हैं।

दिल्ली रैली में जयपुर की दिखेगी ताकतः खाचरियावास

संचार जगत



जयपुर। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास के नेतृत्व में सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र के बनीपार्क ब्लॉक एवं सिविल लाइंस ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में ब्लॉक अध्यक्ष, पार्षद, पार्षद प्रत्याशी, ब्लॉक पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक में 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में राहुल गांधी के आह्वान पर आयोजित होने वाली 'वोट बचाओ, देश बचाओ' रैली को ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया गया। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि सिविल लाइंस विधानसभा के प्रत्येक वार्ड से कम से कम 50 कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचेंगे। हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता बसों, कारों एवं अपने निजी साधनों से दिल्ली कूच करेंगे। जयपुर की प्रत्येक विधानसभा में बैठकों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को एकजुट किया जा रहा है और जयपुर से लगभग 10 हजार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दिल्ली पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है।

स्टेट ग्रोथ के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करें - नमित मेहता



संचार जगत

जयपुर। आबकारी आयुक्त नमित मेहता ने कहा कि प्रदेश सरकार की अपेक्षा के अनुरूप विभागीय राजस्व लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए। आबकारी आयुक्त विडियों कांफ्रेंस के माध्यम से विभागीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विभागीय समीक्षा वीसी में राजस्व अन्य विषयों पर विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक निर्देश प्रदान किए। आबकारी आयुक्त श्री मेहता ने कहा कि प्रदेश में अक्टूबर माह में अब तक कई जिलों की राजस्व प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नही है जिसे कार्ययोजना बनाकर टीमवर्क से पूर्ण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अक्टूबर माह में राजस्व के तहत स्टेट की औसत ग्रोथ 15 प्रतिशत है जिसे कायम रखते हुए अपेक्षित लक्ष्य पूर्ण करना सुनिश्चित करे। स्टेट ग्रोथ से कम की राजस्व प्रगति स्वीकार्य नही है, साथ ही जो जिले नेगेटिव ग्रोथ दर्शा रहे वे इस माह के शेष दिनों के लिए विस्तृत कार्ययोजना एवं सर्कलवार लक्ष्य तय प्रगति सुनिश्चित करेंगे।

पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग आज

संचार जगत

जोधपुर। जोधपुर में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग आज हो रही है। जिला परिषद के 34 वार्डों के लिए 118 प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि 17 पंचायत समितियों में 787 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। प्रशासन ने मतदान की तैयारियां तेज कर दी हैं। ट्रेनिंग के बाद पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुई। आज जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान होगा, जबकि सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव 30 अक्टूबर को कराए जाएंगे। दूसरे चरण में आसोप, बावड़ी, भोपालगढ़, बिलाड़ा, ओसियां, लूणी, मंडोर समेत जिले की 17 पंचायत समितियों में चुनाव होंगे। जिला परिषद के 34 वार्डों के लिए 13 लाख 18 हजार से ज्यादा मतदाता पंजीकृत हैं, वहीं पंचायत समिति चुनाव में 10 लाख 77 हजार से ज्यादा वोटर मतदान करेंगे। इस बार मतदाताओं को दो वोट डालने होंगे। पहले जिला परिषद सदस्य और फिर पंचायत समिति सदस्य के लिए मतदान होगा। पिछले चरण में बाएं हाथ की तर्जनी पर स्याही लगाई गई थी, जबकि इस चरण में दाएं हाथ की तर्जनी पर स्याही लगाई जाएगी।

दशहरा मेले में निकली जनजागरण रैली



संचार जगत

कोटा। वन एवं वन्यजीव संरक्षण के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से जनजागरण रैली का आयोजन किया गया। रैली को मुख्य अतिथि प्रकाश जायसवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में विभिन्न विद्यालयों एवं ओपन यूनिटों के स्काउट-गाइड, कब-बुलबुल तथा रोवर-रेंजर ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आवासन मंडल विद्यालय में एकत्रित होने के बाद सभी प्रतिभागी बसों के माध्यम से डॉल्फिन पार्क पहुंचे, जहां से जनजागरण रैली का शुभारंभ किया गया। रैली दशहरा मेले के विभिन्न बाजारों से होकर गुजरी। इस दौरान प्रतिभागियों ने वन एवं वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण संतुलन, प्रकृति की रक्षा तथा जीव-जंतुओं के प्रति संवेदनशीलता का संदेश दिया। रैली के माध्यम से आमजन को समझाया गया कि वन और वन्यजीव प्रकृति के अभिन्न अंग हैं तथा इनका संरक्षण करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। रैली का समापन श्रीराम रंगमंच पर हुआ। यहां आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए वनों की रक्षा, वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास का संरक्षण तथा पर्यावरण के प्रति जागरूकता का आह्वान किया। निगम की ओर से बच्चों के लिए दशहरा मेले में मनोरंजन की व्यवस्था की गई। बच्चों ने मेले में झूलों, मौत के कुएं सहित विभिन्न आकर्षणों का आनंद लिया।

औद्योगिक विकास में नीमराणा का विशेष महत्वः बागडे





संचार जगत

नीमराणा। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने राइजिंग नीमराणा कार्यक्रम के तहत नीमराणा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के एनआईए एमजी भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने एनआईए सर्किल, एनआईए लेन एवं पर्यावरण मार्ग का शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने उद्योगपतियों के साथ संवाद कर औद्योगिक विकास, सरकारी पहलों और नीमराणा की औद्योगिक महत्ता पर चर्चा की। इस दौरान राज्यपाल बागडे ने औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों एवं पहलों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत प्रदेश की आर्थिक प्रगति और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नीमराणा जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र का राज्य की अर्थव्यवस्था में विशेष महत्व है। औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार के साथ आधारभूत सुविधाओं का विकास तथा सरकार और उद्योग जगत के बीच बेहतर समन्वय भी आवश्यक है। राज्यपाल ने उद्योग जगत के योगदान और औद्योगिक विकास की संभावनाओं के संदर्भ में नीमराणा की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि एनआईए भवन की पहल एसोसिएशन की गतिविधियों के संचालन और क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने मंगलवार को नीमराणा में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न विभागों के कार्यों, विकास योजनाओं एवं जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की समीक्षा की। बैठक में कृषि, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा तथा नशामुक्ति एवं टीबी मुक्त अभियान सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। नशामुक्त भारत अभियान की समीक्षा के दौरान राज्यपाल बागडे ने नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए संबंधित विभागों को समन्वित कार्रवाई करने तथा विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में जन जागरूकता गतिविधियां संचालित करने पर जोर दिया। उन्होंने युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराने और नशामुक्ति के प्रयासों में जनभागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा की प्रत्येक गांव-गांव जाकर नशा मुक्त अभियान को प्रभावी बनायें, निगरानी को सख्त करें, कार्यवाही तेज करने के निर्देश दिए। बागडे ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत रोगियों की समय पर पहचान, नियमित उपचार तथा पात्र मरीजों को पोषण सहायता उपलब्ध कराने एवं टीबी मुक्त अभियान को और अधिक प्रभावी रूप संचालित कर आमजन को ज़मीनी स्तर पर लाभ पहुँचाने में निर्देश दिए।

रंगोली में प्रतिभागियों ने भरे कल्पनाओं के रंग

संचार जगत



कोटा। राष्ट्रीय मेला दशहरा में मेहंदी, मांडणा और रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें प्रतियोगियों ने जमीं पर रंगों से सामाजिक संदेश देते हुए विचारों को प्रतिपादित किया। रंगोली में युवक युवतियों और महिलाओं ने भावनाओं के रंग भरे। प्रतियोगिता में भोपाल की रुचि सराठे प्रथम, झालावाड़ की प्रियंका शर्मा द्वितीय स्थान और कोटा की लेखा राठौर तीसरे स्थान पर रही। मेहंदी में महिलाओं ने भरवां, फूल और धार्मिक चिन्हों से आकर्षक डिजाइनें बनाई। मांडणा में भाग लेने वाली महिलाओं ने कूंची से दीवारों पर राजस्थानी लोक परंपरा को जीवित किया।

आर्म्स एक्ट प्रकरण में सीएसटी का हैड कांस्टेबल गिरफ्तार

जयपुर। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने कहा कि कमिश्नरेट में अनुशासनहीनता और कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने पुलिस उपायुक्त (उत्तर) को तथ्यों को छिपाने, और संदिग्ध व्यक्तियों से अनुचित संबंध रखने वाले सीएसटी के हैड कांस्टेबल पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मंगलवार को शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज एक प्रकरण की जांच के दौरान सीएसटी के हैड कांस्टेबल रोहिताश की भूमिका संधिग्ध होने संबंधित तथ्य सामने आए है।

नगर निगम का दीपावली मेला आज से

संचार जगत



उदयपुर। नगर निगम ने 15 दिवसीय दीपावली मेले की तैयारी पूरी कर ली है। आज से शुरू होने वाला यह मेला न केवल उदयपुर की समृद्ध कला और सांस्कृतिक विरासत को सहेजेगा, बल्कि बॉलीवुड के शीर्ष पार्श्व गायन, स्टैंडअप कॉमेडी और अखिल भारतीय स्तर के प्रखर काव्य-पाठ का अनूठा संगम भी प्रस्तुत करेगा। महापौर पारस सिंघवी और मेला संयोजक प्रमोद सामर ने बताया कि कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी करेंगे इस मेले का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर निम्बार्क पीठ अस्थल आश्रम के मेवाड़ महामंडलेश्वर रासबिहारी शरण भी मौजूद रहेंगे। मेले के दौरान 3 नवंबर तक रंगारंग सांस्कृतिक संध्याएं आयोजित की जाएंगी, जबकि मेले के तहत दुकानें, लजीज खान-पान के स्टॉल और रोमांचक झूले 11 नवंबर तक संचालित रहेंगे। इस आयोजन को संचालित करने के लिए 21 समितियों का गठन किया गया है।

सचिव ने किया राजस्थान सम्पर्क हेल्पलाइन 181 का निरीक्षण

जयपुर। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग तथा आयोजना विभाग के शासन सचिव डॉ. रवि कुमार सुरपुर ने मंगलवार को राजस्थान सम्पर्क हेल्पलाइन 181 का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सम्पर्क एआई की कार्यप्रणाली का जायजा लेते हुए हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों के विश्लेषण, उनके मूल कारणों की पहचान और प्रभावी निस्तारण के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने ऑडियो एवं वीडियो कॉल के माध्यम से परिवादियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं भी सुनीं तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।डॉ. सुरपुर ने आधार एवं जनाधार सेवाओं से संबंधित शिकायतों का सम्पर्क एआई के माध्यम से विश्लेषण कर उनके मूल कारणों की पहचान करने के निर्देश दिए।

सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में स्वच्छता अभियान आयोजित

संचार जगत

जयपुर। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में कायाकल्प गतिविधियों के तहत विशेष अभियान आयोजित किया गया। अभियान का उद्देश्य अस्पतालों में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करना, संक्रमण की रोकथाम सुनिश्चित करना तथा मरीजों के लिए स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना रहा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने कहा कि अस्पतालों में स्वच्छता और साफ-सफाई केवल व्यवस्था का हिस्सा नहीं, बल्कि मरीजों की सुरक्षा और बेहतर उपचार से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं संस्थान प्रमुखों को स्वास्थ्य संस्थानों में नियमित साफ-सफाई, संक्रमण नियंत्रण के निर्धारित प्रोटोकॉल की पालना तथा जैव चिकित्सा अपशिष्ट का नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित करने पर जोर दिया। अभियान के तहत अस्पतालों के अधिक आवाजाही वाले क्षेत्रों, बाह्य रोगी विभागों, वार्डों और सार्वजनिक सुविधाओं की गहन सफाई, हाथों की स्वच्छता संबंधी प्रोटोकॉल की पालना तथा अस्पताल परिसरों में अनावश्यक सामान एवं कबाड़ हटाने जैसी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। साथ ही, अस्पताल परिसर के खुले एवं हरित क्षेत्रों की साफ-सफाई और बेहतर रखरखाव पर भी जोर दिया गया।

ट्रेन छूटने से पहले पकड़ा गया शराब तस्कर

जोधपुर। रेलवे सुरक्षा बल की मंडल टास्क टीम ने जोधपुर रेलवे स्टेशन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ट्रेन के एसी कोच से अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। ट्रेन रवाना होने में जब महज पांच मिनट का समय शेष था, तभी सतर्क जवानों ने ए-1 कोच में सीट के नीचे छिपाकर रखे पांच बैग से 72.75 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद कर ली। बाजार में इस शराब की कीमत करीब 1 लाख 3 हजार 150 रुपये आंकी गई है। आरपीएफ ने पाली निवासी आरोपी को गिरफ्तार कर अग्रिम कानूनी कार्रवाई के लिए राजकीय रेलवे पुलिस के हवाले कर दिया है। रवानगी से ठीक पहले खुला राजः बर्थ नंबर 17 के नीचे लावारिस दिखे बैगघटना 26 अक्टूबर की रात करीब 9:55 बजे की है।

मोबाइल एसोसिएशन ने जीओ डिस्टीब्यूटर की मनमानी के खिलाफ दिया ज्ञापन



संचार जगत

कोटा। जिओ कंपनी द्वारा मोबाइल दुकानदारों पर अनावश्यक दबाव बना करके उनकी व्यापारिक सिम को बंद करके जबरदस्ती दबाव डाला जा रहा है। सभी दुकानदारों से स्टांप पर एग्रीमेंट करवा करके कई नियम व शर्तों से बांधा गया। किंतु कंपनी और डिस्टीब्यूटर के प्रतिनिधि मंडी नगर के बाहर और गांवों में छतरी और कैनोपी लगा करके फ्री में सिम देने और एमएनपी के साथ गिफ्ट देने का लालच दे रहे हैं। इस मामले में इनको बंद करवा के व्यापारियों से बिना दबाव के कार्य करवाने की मांग करते हुए मोबाइल एसोसिएशन के रिटेलरों ने पुलिस उपअधीक्षक से मुलाकात की। उन्होंने अपनी समस्या से अवगत कराते हुए ज्ञापन दिया। ज्ञापन में 5 सूत्री मांग का जिक्र किया गया हे। उप अधीक्षक व्यापारियों का आश्वस्त किया है कि शीघ्र ही कैनेपी और छतरी हटवाई जाएगी। व्यापारियों ने कहा कि यदि फिर भी डिस्ट्रीब्यूट की मनमानी जारी रहती है तो जिओ के खिलाफ राज्य व्यापी बहिष्कार किया जाएगा।

दशहरा मैदान अब 12 महीने रहेगा रोशन, जल्द शुरू होगा नाइट बाजार



संचार जगत

कोटा। देश के बड़े महानगरों की तर्ज पर अब कोटा के दशहरा मैदान में जल्द ही नाइट बाजार शुरू होने जा रहा है। इससे यह परिसर अब पूरे साल जगमग रहेगा। नगर निगम ने विजयश्री रंगमंच के पास 400 फीट लंबी सुरक्षा ग्रिल, खूबसूरत फाउंटेन, आकर्षक लाइटिंग और लोगों के बैठने के लिए बेंचों के साथ इस पूरे मार्केट की तैयारियां पूरी कर ली हैं। ग्राहकों की सुविधा के लिए परशुराम द्वार को मुख्य प्रवेश और निकास रास्ता बनाया गया है। अब तक सिर्फ हर साल होने वाले दशहरा मेले तक सीमित रहने वाले इस परिसर की 200 खाली दुकानों का स्थायी और नाइट मार्केट के रूप में उपयोग होने से जहां सुरक्षा और रखरखाव बेहतर होगा, वहीं निगम को भी हर महीने भारी राजस्व मिलेगा, जिसकी अंतिम रूपरेखा और संचालन दशहरे के बाद तय किया जाएगा।

नतीजे से पहले मनाया जीत का जश्न, मिली हार तो छाया सन्नाटा

संचार जगत



नागौर। माडपुरा गांव से पंचायती राज चुनाव का एक दिलचस्प और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। चुनाव परिणाम के आधिकारिक नतीजे आने से पहले सरपंच पद की प्रत्याशी मगी देवी के समर्थकों ने तीन घंटे पहले ही जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया था। मतगणना के दौरान रात करीब साढ़े ग्यारह बजे यह अफवाह फैल गई कि मगी देवी चुनाव जीत गई हैं। जिसके बाद बिना किसी आधिकारिक पुष्टि या रिटर्निंग ऑफिसर के सर्टिफिकेट का इंतजार किए अति उत्साही समर्थकों ने ढोल-नगाड़ों की थाप पर उन्हें साफा और फूलों की मालाएं पहनाकर गांव की गलियों में विजयी जुलूस निकाल दिया, पटाखे फोड़े और मिठाइयां बांटीं। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई, क्योंकि रात करीब ढाई बजे जब मतगणना पूरी होने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने आधिकारिक आंकड़े जारी किए, तो असली तस्वीर सामने आ गई और सबके होश उड़ गए। आधिकारिक परिणामों के अनुसार प्रतिद्वंद्वी प्रत्याशी रूपी बाई को 1581 वोट मिले, जबकि मगी देवी को 1412 वोट ही मिल सके और रूपी बाई ने 169 वोटों के अंतर से यह चुनाव जीत लिया। नतीजा आते ही जश्न मना रहे समर्थकों में सन्नाटा छा गया और वे चुपचाप वहां से खिसक गए, जबकि विजेता रूपी बाई के समर्थकों ने अपनी जीत का जश्न मनाया।

ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूजडे कार्यक्रम में विद्यार्थियों को दी कानूनी जानकारी

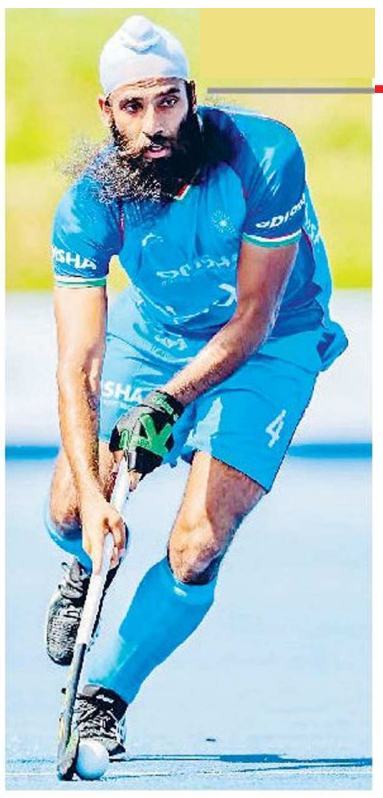
टोंक। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में विवेक विद्या निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूजडे कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गजपाल सिंह ने विद्यार्थियों को कानून, कानूनी प्रक्रियाओं तथा नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों को कानून के प्रति जागरूक रहने, अपने अधिकारों को समझने तथा सामाजिक जीवन में कानूनी नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में कानूनी जागरूकता बढ़ाना और उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रोत्साहित करना रहा।

पंचायतीराज आम चुनाव के द्वितीय चरण के मतदान के लिए मतदान दल रवाना



संचार जगत

जयपुर। पंचायतीराज चुनाव के द्वितीय चरण के तहत जयपुर जिले की पांच पंचायत समितियों एवं जिला परिषद के वार्डों में आज होने वाले मतदान के लिए मंगलवार सुबह श्री भवानी निकेतन फार्मेसी कॉलेज परिसर से मतदान दल अंतिम प्रशिक्षण के उपरांत ईवीएम एवं निर्वाचन संबंधी आवश्यक सामग्री के साथ निर्धारित मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुए। मतदान दलों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चुनाव सामग्री उपलब्ध कराई गई। सामग्री प्राप्त करने के बाद दल अपने संबंधित मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुए। मतदान दलों की सुविधा के लिए वाहन पार्किंग एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मतदान केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष, स्वतंत्र, सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने बताया कि मतदान दलों एवं मतदाताओं की सुविधाओं के लिए सभी मतदान केंद्रों पर शुद्ध पेयजल, शौचालय, स्वच्छता, विद्युत की निर्बाध आपूर्ति सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित किया गया है। द्वितीय चरण में अमरसर, आमेर, जालसू, रामपुरा डाबड़ी एवं शाहपुरा पंचायत समितियों के 81 वार्डों तथा जिला परिषद के वार्ड संख्या 11 से 14 एवं 51 से 57 में मतदान होगा। इन क्षेत्रों में कुल 413 मतदान केंद्र निर्धारित किए गए हैं।



लॉस एंजिलिस ओलंपिक तक टीम में रहना चाहते हैं जरमनप्रीत

नई दिल्ली/संचार जगत

हॉकी इंडिया ने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी (एसीटी) के बाद जिन चार सीनियर खिलाड़ियों को बाहर करने की योजना बनाई है उनमें जरमनप्रीत सिंह भी शामिल हैं लेकिन इस डिफेंडर का अभी संन्यास लेने का मूड नहीं है और उनकी नजरें 2028 में लॉस एंजिलिस में होने वाले ओलंपिक खेलों पर टिकी हैं।

हॉकी इंडिया के सूत्रों ने इस महीने की शुरुआत में बताया था कि जरमनप्रीत, मनदीप सिंह, अमित रोहिदास और नीलकांत शर्मा एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के रूप में भारत के लिए अपना अंतिम टूर्नामेंट खेलेंगे। भारत ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर लिया है।

मैं खेलना जारी रखना चाहता हूं: जरमनप्रीत

अमृतसर के रहने वाले 30 वर्षीय जरमनप्रीत ने कहा, ''मैं खेलना जारी रखना चाहता हूं और लॉस एंजिलिस ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करना चाहता हूं। मैं टीम के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहता हूं।''उन्होंने कहा, ''एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करना हमारी टीम के लिए बड़ी उपलब्धि है।

टीम ने इस बारे में कोई चर्चा नहीं की : हरमनप्रीत



हरमनप्रीत ने सोमवार को टूर्नामेंट पूर्व संध्या पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ''मुझे नहीं लगता कि यह सही खबर है और हमने टीम में इस बारे में कोई चर्चा नहीं की। मुझे लगता है कि यह महज अफवाह है।''जरमनप्रीत ने अब तक 171 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं।

संन्सास की अटकलों को खारिज किया

यह हमारे लिए शानदार अवसर है और हम लॉस एंजिलिस ओलंपिक के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।'' जरमनप्रीत ने कहा, ''इस टूर्नामेंट के बाद हम ओलंपिक के लिए अपनी तैयारी शुरू करेंगे। मैं चाहता हूं कि टीम वहां अच्छा प्रदर्शन करे और स्वर्ण पदक जीते।''भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने भी संन्यास की अटकलों को खारिज करते हुए इसे 'अफवाह' करार दिया।

पेरिस ओलंपिक में टीम के प्रमुख सदस्य रहे : वह पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम के एक प्रमुख सदस्य थे। वह 2022 और 2026 में एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम का भी हिस्सा थे। अर्जुन पुरस्कार विजेता का मानना है कि उन्होंने एक डिफेंडर के रूप में अपने खेल में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं।

खेल में सुधार की कोशिश करता रहूंगा

जरमनप्रीत ने कहा, ''मैंने अपने रक्षात्मक कौशल को बेहतर बनाने, अच्छे अवसर पैदा करने और टीम की जीत में योगदान देने की कोशिश की है। मैं एक डिफेंडर के रूप में अपने खेल में लगातार सुधार करने की कोशिश करता रहूंगा।''

खबर संक्षेप



काजल व नीलम ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई

अस्ताना। भारतीय महिला कुश्ती खिलाड़ियों ने मंगलवार को विश्व चैंपियनशिप में नया इतिहास रचा जब पदार्पण कर रही काजल ढोचक और नीलम सिरोही ने स्वर्ण पदक के मुकाबलों में जगह बनाकर सुनिश्चित किया कि पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के एक ही सत्र में देश की दो महिला पहलवान विश्व खिताब के लिए चुनौती पेश करेंगी। छब्बीस साल की नीलम ने 50 किग्रा वर्ग में कजाखस्तान की जेनेप बायानोवा को 7-3 से हराकर फाइनल में जगह बनाई जहां उनका सामना जापान की दिग्गज पहलवान यूई सुसाकी से होगा। वह विश्व चैंपियनशिप के खिताबी मुकाबले में पहुंचने वाली भारत की दूसरी महिला पहलवान बन गईं। इसके तुरंत बाद 18 वर्षीय काजल ने भी यह उपलब्धि हासिल कर ली। उन्होंने 76 किग्रा वर्ग के सेमीफाइनल में किर्गिस्तान की अनुभवी पहलवान आइपेरी मेडेट काइजी को 10-7 से हराकर शानदार वापसी की।

राष्ट्रीय बधिर टी-20 चैंपियनशिप सूरत में

सूरत। भारतीय बधिर क्रिकेट संघ (आईडीसीए) यहां 10वीं राष्ट्रीय टी20 चैंपियनशिप का आयोजन कर रहा है, जिसमें 14 टीमें भाग ले रही हैं। सूरत बधिर क्रिकेट एसोसिएशन (डीसीएएस) के सहयोग से आयोजित की जा रही यह चैंपियनशिप सोमवार से शुरू हुई और एक नवंबर तक चलेगी। इसके मैच बावाजी क्रिकेट ग्राउंड में आयोजित किए जा रहे हैं। इस बार आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मुंबई, विदर्भ, राजस्थान, छत्तीसगढ़, केरल, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और उत्तर प्रदेश की टीमें इसमें भाग ले रही हैं।

न्यूजीलैंड को छह विकेट से हराया, पांच मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजय बढ़त बनाई

अभिषेक के तूफानी शतक से भारत ने न्यूजीलैंड से टी-20 श्रृंखला जीती



अभिषेक शर्मा
प्लेयर ऑफ द मैच
113 रन
38 गेंद
09 चौके
11 छक्के

- अभिषेक ने महज 38 गेंदों में 113 रन की पारी खेली
- भारत ने 199 रन का लक्ष्य केवल 13.2 ओवर में चार विकेट खोकर पाया
- वैभव ने भी 19 गेंद में 45 रन की शानदार पारी खेली



नई दिल्ली/संचार जगत

अभिषेक शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी के सामने न्यूजीलैंड के गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आए और भारत ने मंगलवार को तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में न्यूजीलैंड को 40 गेंद शेष रहते छह विकेट से हराकर पांच मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली। दुनिया के शीर्ष रैंकिंग वाले टी-20 बल्लेबाज अभिषेक ने महज 38 गेंदों पर 113 रन की अविश्वसनीय पारी खेल प्लेयर ऑफ द मैच बने, उन्होंने केवल 15 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर न्यूजीलैंड की गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा दीं भारत ने 199 रन के मुश्किल दिख रहे लक्ष्य को महज 13.2 ओवर में चार विकेट खोकर हासिल कर लिया।

35 गेंदों में पूरा किया शतक

अभिषेक की विस्फोटक पारी के सामने युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी (19 गेंद में 45 रन) की शानदार बल्लेबाजी भी कई मौकों पर फीकी नजर आई। अभिषेक ने 35 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। शतक लगाने के बाद उन्होंने अपने चिर-परिचित अंदाज में ध्यान मुद्रा बनाकर जश्न मनाया।

भारत ने पावर प्ले में विश्व रिकॉर्ड बनाया

भारत ने इसके साथ ही पांच ओवर में सबसे तेज टीम शतक और टी-20 अंतरराष्ट्रीय में पावरप्ले के दौरान सर्वोच्च स्कोर का विश्व रिकॉर्ड बनाया। अभिषेक और सूर्यवंशी ने पहले विकेट के लिए महज सात ओवर में 133 रन जोड़ दिए।

दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 12 छक्के लगाए

वेलिंगटन के वेस्टपैक ट्रस्ट स्टेडियम में मौजूद दर्शकों के लिए यह साझेदारी लंबे समय तक यादगार रहेगी। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 12 छक्के लगाए। सूर्यवंशी ने चार तो वहीं अभिषेक ने आठ छक्के जड़े। जब ग्लेन फिलिप्स ने अभिषेक का कैच लपका, तब तक भारतीय बल्लेबाज 11 छक्के और नौ चौके लगा चुका था।

अभिषेक की बल्लेबाजी से न्यूजीलैंड का मनोबल टूटा

अभिषेक के विकेट के बाद न्यूजीलैंड की टीम का मनोबल इस कदर टूट चुका था कि उसके खिलाड़ी विकेट मिलने का जश्न मनाने के लिए भी उत्साहित नजर नहीं आए। भारतीय पारी की शुरुआत जैकब डफी के ओवर में 26 रन के साथ हुई। एडम मिल्ने ने दूसरे ओवर में 17 रन दिए। इसके बाद माइकल ब्रेसवेल और काइल जैमीसन ने क्रमशः 21 और 20 रन लुटाए। चार ओवर के भीतर ही न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर के चेहरे पर बेबसी साफ दिखाई देने लगी थी। न्यूजीलैंड की पारी के दौरान गेंद जिस पिच पर रुककर आ रही थी, वही भारतीय बल्लेबाजों के सामने बेहद सपाट नजर आई। अभिषेक और सूर्यवंशी ने गेंद की लाइन से हटकर ऑफ साइड में जगह बनाई या फिर गेंद की दिशा के अनुरूप लेग साइड में जोरदार प्रहार किए।

पावर प्ले के छह ओवर में 118 रन बनाए

भारत ने इस जीत के साथ न्यूजीलैंड की धरती पर लगातार तीसरी टी-20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला जीतने की उपलब्धि हासिल की। इससे पहले भारतीय टीम ने 2020 में 5-0 और 2022 में 1-0 से श्रृंखला अपने नाम की थी। महज 15 साल के सूर्यवंशी ने भी आक्रामक पारी खेली। दोनों ने मिलकर भारतीय टीम को पांच ओवर में 100 रन के पार पहुंचाया और पावरप्ले के छह ओवर में रिकॉर्ड 118 रन बनाए।

स्कोर बोर्ड

न्यूजीलैंड पारी	रन	गेंद	4	6
टिम सीफर्ट का अक्षर बो अर्शदीप	02	06	0	0
फिन एलन का नवाब बो हेर्शे	40	25	0	5
डैरिल मिचेल नाबाद	89	52	5	5
ग्लेन फिलिप्स का एवं बो अक्षर	17	14	3	0
केन विलियमसन नाबाद	39	23	4	1
अतिरिक्त: 11, कुल योग : 20 ओवर में 198/3 रन				
विकेट पतन: 1-4, 2-90, 3-123				
गेंदबाजी: भुवनेश्वर 4-0-40-0, अर्शदीप 4-0-33-1, हिस यादव 4-0-44-0 अक्षर 4-0-36-1, हेर्शे 4-0-38-1				
भारत पारी	रन	गेंद	4	6
वैभव सूर्यवंशी का मिचेल बे मिल्ने	45	19	4	4
अभिषेक का फिलिप्स बो जैमीसन	113	38	9	11
तिलू तैमसन बे जैमीसन	18	13	2	0
श्रेयस अय्यर का फिलिप्स बे सैंटनर	05	10	0	0
हार्दिक पांड्या नाबाद	01	01	0	0
नमन धीर नाबाद	04	01	1	0
अतिरिक्त : कुल योग: 13.2 ओवर में 199/4 रन				
विकेट पतन: 1-133, 2-178, 3-193, 4-195				
गेंदबाजी: डफी 2-0-44-0, मिल्ने 2-0-33-0, ब्रेसवेल 2-0-36-0, जैमीसन 3.2-0-45-2 सैंटनर 1-0-23-1, सैंटनर 3-0-17-1				



वनडे में भी क्लीन स्वीप करने उतरेगी टीम इंडिया

वडोदरा। टी20 में क्लीन स्वीप करने वाली भारतीय टीम अपना विजय अभियान जारी रखकर जिम्बाब्वे के खिलाफ बुधवार को यहां होने वाले तीसरे और अंतिम महिला एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भी इसे दोहराने की कोशिश करेगी। पहले दो मैचों में जीत के बाद भारत ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। अब उसका लक्ष्य क्लीन स्वीप करना होगा, जो टी20 सीरीज में 3-0 की जीत के बाद एक और बड़ी उपलब्धि होगी। भारत को पहले दो वनडे मैच में किसी तरह की खास चुनौती नहीं मिली। पहले मैच में प्रतिका रावल के नाबाद शतक और श्री चरणी के चार विकेट की बदौलत भारत ने नौ विकेट से जीत हासिल की। दूसरे मैच में हरमनप्रीत कौर के 126 और दीप्ति शर्मा के नाबाद 106 रन की मदद से भारत ने छह विकेट पर 328 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने पूर्णकालिक कप्तान बनने के बाद टीम को अच्छी सफलता दिलाई है लेकिन वह बल्लेबाजी में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाई हैं। ऐसे में वह अंतिम मैच में बड़ी पारी खेलने के लिए प्रतिबद्ध होंगी।

श्रीलंका ने पाक को 8 विकेट से हराया

इंग्लैंड त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल की दौड़ से बाहर

नई दिल्ली/संचार जगत

श्रीलंका ने मंगलवार को पाकिस्तान को आठ विकेट से करारी शिकस्त देकर इंग्लैंड की त्रिकोणीय एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के फाइनल में जगह बनाने की उम्मीदों को खत्म कर दिया। तेज गेंदबाज दिलशान मदुशंका ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 34 रन देकर पांच विकेट झटके जिससे टॉस गंवाने के बाद बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम सिर्फ 110 रन पर सिमट गई।

श्रीलंका ने इसके बाद 18.1 ओवर में दो विकेट पर 114 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। यह मुकाबला दिन-रात का था और गद्दाफी स्टेडियम की फ्लडलाइट के पूरी तरह जलने से पहले ही श्रीलंकाई टीम जीत दर्ज कर चुकी थी। श्रीलंका ने इससे पहले रावलपिंडी में इंग्लैंड के खिलाफ 430 रन के लक्ष्य का पीछा करके एकदिवसीय इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल किया था। श्रीलंका की ओर से कामिंदु मेंडिस ने 60 गेंद में नाबाद 62 रन बनाए। उन्हें खाता खोलने से पहले ही विकेटकीपर ने जीवनदान दे दिया था। इसके अलावा 44 रन के निजी स्कोर पर उन्होंने रिव्यू लेकर मैदानी अंपायर के पगबाधा के फैसले को पलटवा दिया। बायें हाथ के इस बल्लेबाज ने अपनी पारी में आठ चौके और दो छक्के लगाए।



विश्व अंडर-19 मुक्केबाजी

आदित्य ने 55 किग्रा में जीता स्वर्ण, मेघा को रजत

नई दिल्ली/संचार जगत

एशियाई चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता आदित्य ने मंगलवार को मोंटेनेग्रो के बुडवा में विश्व मुक्केबाजी अंडर-19 चैंपियनशिप में पुरुषों के 55 किग्रा वर्ग का खिताब अपने नाम किया।

शुरुआती राउंड में मामूली अंतर से पिछड़ने के बाद भारतीय मुक्केबाज ने शानदार वापसी करते हुए फाइनल में रूस के इस्लाम मागोमेदोव को 4-1 से हराया। भारत ने प्रतियोगिता में एक स्वर्ण, एक रजत और दो कांस्य पदक सहित कुल चार पदक जीते। जीत के बाद आदित्य ने कहा, ''मैं पहले राउंड के बाद 2-3 से पिछड़ रहा था लेकिन मैंने अगले राउंड में बेहतर प्रदर्शन करते हुए इसे 4-1 से अपने नाम किया। तभी मुझे विश्वास हुआ कि मैं यह मुकाबला जीत सकता हूं।''

हालांकि दूसरे स्वर्ण पदक की भारत की उम्मीदों को झटका लगा जब महिला 80 किग्रा वर्ग के फाइनल में मेघा श्योकंद को रूस की एकातेरिना फ्रोलोवा के खिलाफ 0-5 से हार का सामना करना पड़ा। भारत के दो कांस्य पदक हर्षिका (महिला 65 किग्रा) और प्राची टोकस (महिला 80 किग्रा से अधिक) ने जीते।

गुजरना पड़ेगा कड़ी जांच से

वाडा ने आईसीसी को टियर-1 में रखा, भारत शीर्ष श्रेणी में बरकरार

- आईसीसी अब तक टियर-2 पर थी
- खिलाड़ियों को अब अधिक कड़ी जांच से गुजरना पड़ेगा

नई दिल्ली/संचार जगत

विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) ने क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किए जाने के मद्देनजर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) को अपनी प्राथमिकता नीति के तहत पहली श्रेणी में शामिल कर दिया है, जबकि भारत उन शीर्ष देशों में बना हुआ है जिन्हें संस्था के निगरानी कार्यक्रम में सबसे कड़ी जांच का सामना करना पड़ता है। आईसीसी अब तक टियर2 पर थी, लेकिन अब उसे टियर1 में रख दिया गया है जिसमें खिलाड़ियों को अधिक कड़ी जांच से गुजरना पड़ता है। यह व्यवस्था अगले वर्ष एक जनवरी से लागू होगी। वाडा ने कहा, ''खेलों के वर्गीकरण का आधार यह है कि क्या खेल ओलंपिक या पैरालंपिक कार्यक्रमों में शामिल हैं।'' क्रिकेट 100 से अधिक वर्षों के बाद 2028 में लॉस एंजिलिस ओलंपिक खेलों में वापसी करेगा। इस स्तरीय प्रणाली का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वाडा के संसाधनों का उपयोग उन देशों और खेलों में डोपिंग के जोखिम का सामना करने के लिए किया जा सके जहां धोखाधड़ी का जोखिम और प्रभाव सबसे अधिक माना जाता है। वाडा के 38 सदस्यीय शीर्ष स्तर में अन्य प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संघों में विश्व बैडमिंटन महासंघ, अंतरराष्ट्रीय साइकिलिंग संघ, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ, अंतरराष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ, अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति, अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ, वर्ल्ड बॉक्सिंग और विश्व एथलेटिक्स शामिल हैं।

भारत स्क्वाश में शीर्ष श्रेणी में शामिल हुआ

ओलंपिक खेलों में स्क्वाश को शामिल किए जाने के कारण विश्व स्क्वाश महासंघ को भी टियर3 से टियर1 में रखा गया है। इस बीच डोपिंग के अधिक मामले पाए जाने के कारण भारत पिछले तीन वर्षों से शीर्ष श्रेणी में बना हुआ है। इस श्रेणी में कुल 50 देश शामिल हैं जिनमें अमेरिका और चीन भी हैं।
हर दो साल में अपडेट करेगा : वाडा हर दो साल में स्तर (टियर) को अपडेट करेगा और इससे जुड़े देशों और खेल संघों को उनकी स्थिति में बदलाव होने पर कम से कम दो महीने का नोटिस मिलेगा।

केन ने पिछले सत्र में क्लब की और से देश के लिए 73 गोल किए, महिला वर्ग में पुटेलस को तीसरा खिताब

केन 25 वर्षों में बैलोन डी ओर जीतने वाले इंग्लैंड के पहले खिलाड़ी बने

नई दिल्ली/संचार जगत

पिछले सत्र में शानदार प्रदर्शन करने वाले हैरी केन पिछले 25 वर्षों में बैलोन डी ओर जीतने वाले इंग्लैंड के पहले खिलाड़ी बन गए हैं जबकि महिला वर्ग में स्पेन की स्टार खिलाड़ी एलेक्सिया पुटेलस ने तीसरी बार यह प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीती। केन ने पिछले सत्र में क्लब और देश के लिए 73 गोल किए और वह यूरोप में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी रहे। केन ने जर्मनी के अपने क्लब बायर्न म्यूनिख और विश्व कप में गोल करने का नया रिकॉर्ड बनाया था। विश्व कप में वह इंग्लैंड के कप्तान थे और उनकी टीम तीसरे स्थान पर रही थी। इस 33 वर्षीय खिलाड़ी ने इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुने जाने के बाद कहा, ''कड़ी मेहनत से सब कुछ संभव है। मेरा सफर आसान नहीं था। मैं वो बच्चा नहीं था जो सीधे शिखर पर पहुंच गया हो। मुझे उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ा।''

विश्व कप में केन ने छह गोल दागे थे

विश्व कप में उन्होंने छह गोल करके गैरी लाइनकर को पीछे छोड़ते हुए इंग्लैंड की तरफ से विश्व कप में सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड बनाया था। उनकी टीम सेमीफाइनल में अर्जेंटीना से हार गई, लेकिन उसने तीसरे स्थान के मैच में फ्रांस को हराया जो पिछले 60 वर्षों में इंग्लैंड का विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।



पुटेलस ने 2021 व 2022 में यह पुरस्कार जीता

पुटेलस ने 2021 और 2022 में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता था। महिलाओं के लिए इस पुरस्कार की शुरुआत 2018 में हुई थी। उन्होंने पुरस्कार के लिए चुने जाने के बाद युवा खिलाड़ियों के लिए संदेश में कहा, ''खुद पर विश्वास रखो। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर आपका कोई सपना है, तो उसे पूरा करने की कोशिश करो, भले ही कभी-कभी आपको शून्य से शुरुआत करनी पड़े।''

केन के बाद एमबाप्पे का नंबर रहा

केन ने कहा, ''मुझे इस मुकाम पर पहुंचने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा। मुझे उम्मीद है कि इससे युवा खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी।''इस पुरस्कार की दौड़ में शामिल अन्य खिलाड़ियों में मतदान में केन के बाद किलियन एमबाप्पे, लामिन यामल (जिन्हें लगातार तीसरे वर्ष सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी चुना गया), 2024 के विजेता रोड्रि और रिकॉर्ड आठ बार के विजेता लियोनेल मेस्सी का नंबर रहा।

सुको में एसआईआर और सीईसी के संबंध में सुनवाई पूरी

चुनाव आयोग के हलफनामे पर जवाब देने को याचिकाकर्ताओं को 10 दिन की मोहलत दी, फॉर्म-6 में बदलाव पर ईसी से मांगा जवाब

नई दिल्ली/संचार जगत

सुप्रीम कोर्ट में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर दायर याचिकाओं पर मंगलवार की सुनवाई पूरी हो गई है। चुनाव आयोग की तरफ से दाखिल हलफनामे पर जवाब देने के लिए याचिकाकर्ताओं ने सर्वोच्च अदालत से 10 दिन का समय मांगा है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की इस मांग को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी अतिरिक्त हलफनामे के लिए 14 दिन का समय दिया है। इस मामले की सुनवाई सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3सदस्यों वाली बेंच ने की। बेंच में जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल हैं





नई याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस

उच्चतम न्यायालय ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान फॉर्म-6 में बदलाव करने का निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाने वाली सांसद डोला सेन की नई याचिका पर आयोग को नोटिस जारी किया।

एकतरफा निर्णय लेने के आरोप लगाए

याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने एसआईआर की प्रक्रिया से जुड़े फैसले लेते समय चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की राय को नजरअंदाज किया। इस दौरान एकतरफा और मनमाने तरीके से निर्णय लिए गए। याचिकाओं में नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 के साथ अतिरिक्त घोषणा पत्र जोड़ने के फैसले पर भी सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस शर्त के कारण नए और युवा मतदाताओं के लिए मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराना मुश्किल हो सकता है।

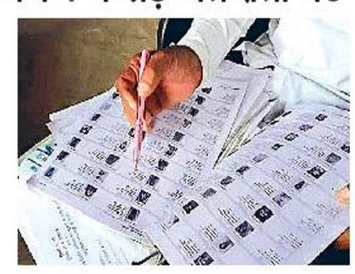
चुनाव आयोग ने सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में इन आरोपों को खारिज किया है। आयोग के अनुसार एसआईआर से संबंधित तीनों आदेश सर्वसम्मति से जारी किए गए थे। उनमें इसे लेकर कोई आपसी मतभेद नहीं था। आयोग ने स्पष्ट किया कि इन फैसलों में किसी तरह की एकतरफा कार्रवाई नहीं की गई।

कर्नाटक में फाइनल वोटर लिस्ट जारी

एसआईआर के बाद लगभग 1 करोड़ मतदाता घटे

बेंगलुरु। कर्नाटक में एसआईआर) 27 अक्टूबर को पूरा हुआ। इसके चलते राज्य के मूल 5.5 करोड़ मतदाताओं की सूची से लगभग 99.76 लाख मतदाता कम हो गए हैं, जिससे अब कुल मतदाताओं की संख्या 4,54,55,689 यानी 4.54 रह गई है। इनमें से लगभग 86.56 लाख मतदाता 20-29 आयु वर्ग के हैं, जबकि नए मतदाताओं की संख्या 6.83 लाख है। 16 जून को, जब प्रक्रिया के लिए मतदाता सूची के फ्रीज कर किया गया था, तब राज्य में लगभग 5.5 करोड़ मतदाता थे। इसके बाद हुई जांच प्रक्रिया के दौरान, 24 अगस्त को जारी ड्राफ्ट सूची में लगभग



19.48 प्रतिशत यानी 1.08 करोड़ मतदाताओं को हटा दिया गया। इन्हें अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत, डुप्लिकेट और अन्य श्रेणी में रखा गया था।

डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स की याचिका पर केंद्र को नोटिस

डेटा प्रोटेक्शन कानून के खिलाफ 21 मीडिया ग्रुप पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली/संचार जगत

21 प्रमुख डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स ए सो सि ए श न (डीएनपीए) ने सुप्रीम कोर्ट में 'डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट' को चुनौती दी है। संगठन का तर्क है कि इस कानून में पत्रकारिता के लिए कोई छूट न होने से खोजी पत्रकारिता और गोपनीय स्रोतों की सुरक्षा पर खतरा पैदा हो सकता है। एसोसिएशन ने यह भी कहा है कि कानून में सरकारी संस्थाओं को छूट दी गई है, जबकि पत्रकारिता के लिए वैसी सुरक्षा नहीं है। इस कानून के कई कड़े प्रावधान मई 2027 से लागू होने वाले हैं। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जवाब तलब किया।

■ कहा- इस कानून से खबरों की रिपोर्टिंग करना मुश्किल होगा

याचिका दायर करने वालों में अंबानी और अदानी समूह भी शामिल

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने हालांकि, सरकार का पक्ष सुने बिना कानून पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर 2026 को होगी। याचिका दायर करने वाले 21 समाचार प्रकाशकों में मुकेश अंबानी के रिलायंस समूह की नेटवर्क18, गौतम अडानी समूह की एनडीटीवी, द इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स इंटरनेट, द हिंदू, इंडिया टुडे, जी मीडिया और एबीपी सहित अन्य मीडिया संस्थान शामिल हैं।

निजता और प्रेस की स्वतंत्रता में संतुलन जरूरी

डीएनपीए की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता माधवी दीवान ने दलील दी कि पत्रकारिता को स्पष्ट छूट नहीं देना प्रेस पर पूर्व-नियंत्रण जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। उन्होंने कहा कि खबर



प्रकाशित करने से पहले संबंधित व्यक्ति की अनुमति लेने की बाध्यता न्यूजरूम के कामकाज को प्रभावित करेगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि मीडिया संस्थानों को व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग को रोकने के उपाय भी सुझाने चाहिए। उन्होंने टिप्पणी की कि निर्दोष नागरिकों के भी अधिकार हैं और निजता तथा प्रेस की स्वतंत्रता के बीच संतुलन स्थापित करना आवश्यक है।

यह जताई चिंता

सहमति की शर्त से होगी पत्रकारिता प्रभावित

डीएनपीए के मुताबिक, किसी व्यक्ति की निजी जानकारी इस्तेमाल करने से पहले उसकी सहमति लेना जरूरी होने से खोजी पत्रकारिता प्रभावित हो सकती है। अगर पत्रकार जांच के बारे में संबंधित व्यक्ति को पहले ही बता दें, तो वह सबूत नष्ट कर सकता है या गवाहों को डरा सकता है।

पत्रकारों के गोपनीय सूत्रों की पहचान उजागर होने का खतरा

डीएनपीए ने सरकार को संगठनों से जानकारी मांगने की शक्तियां दिए जाने पर सवाल उठाए हैं। एसोसिएशन का कहना है कि इन शक्तियों के इस्तेमाल से पत्रकारों के गोपनीय सूत्रों की पहचान उजागर हो सकती है। इससे भ्रष्टाचार, कॉर्पोरेट गड़बड़ियों और चुनावी अनियमितताओं की जानकारी देने वाले लोगों पर भी असर पड़ सकता है।

प्रकाशित खबरें हटाने का दबाव बन सकता है

याचिका में कहा गया है कि कानून के तहत व्यक्ति अपनी सहमति वापस लेकर निजी जानकारी मिटाने की मांग कर सकता है। एसोसिएशन को आशंका है कि इससे प्रकाशित खबरें हटाने या उनमें बदलाव करने की मांग की जा सकती है। याचिका के मुताबिक, कानून में सार्वजनिक हित की खबरों के लिए पर्याप्त सुरक्षा नहीं है।

मुस्कान-साहिल की फांसी पर अब 30 को सुनवाई

मेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ के बहुचर्चित नीले ड्रम हत्याकांड में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई।



सौरभ राजपूत हत्याकांड में दोषी ठहराए गए मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला की ओर से दाखिल याचिका पर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने संवेदनशीलता को देखते हुए अगली सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तारीख दी है।

मोइत्रा ने हाई कोर्ट से कहा, 'हटा दूंगी पोस्ट'

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि वे भाजपा सांसद



निशिकांत दुबे पर की गई विवादित टिप्पणी सोशल मीडिया से हटा देंगी। महुआ के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि का केस किया किया है। पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग के खिलाफ भी केस किया है।

मिजोरम में एक किलो मेथामफेटामाइन बरामद

आइजोल। मिजोरम के आइजोल जिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके पास से एक किलोग्राम



मेथामफेटामाइन बरामद किया गया है। मंगलवार को पुलिस ने बताया कि सोमवार को ब्वांगकॉन थाना क्षेत्र में जेमाबॉक वन जांच चौकी के पास एक वैन को रोककर तलाशी ली गई,

एसआईआर से पहले कर्नाटक में थे 5.54 करोड़ मतदाता

कर्नाटक में एसआईआर के बाद कटे 1 करोड़ नाम, अमेठी में कई जिंदा के नाम गायब

कर्नाटक में एसआईआर प्रक्रिया के तहत फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, लगभग 1.08 करोड़ मतदाताओं का नाम फाइनल रोल से हटा दिया गया। ऐसा एन्यूमरेशन फॉर्म जमा न होने के कारण हुआ है, जो कुल वोटरों का करीब 19.48 प्रतिशत हिस्सा है। इधर, अमेठी, यूपी में 200 जिंदा लोगों के नाम गायब हैं जबकि 4 दर्जन मृतकों के नाम दर्ज हैं।

नई दिल्ली/संचार जगत

कर्नाटक में चुनाव आयोग की जांच और सुनवाई की प्रक्रिया के बाद 61,867 लोगों को फाइनल वोटर लिस्ट के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। वहीं, कुल 4.46 करोड़ मतदाताओं को शामिल किया गया है। वोटर लिस्ट को पूरी तरह से सटीक और पारदर्शी बनाने के मकसद से चुनाव आयोग ने बड़े पैमाने पर एएसडीडी- अनुपस्थित, स्थायी रूप से स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान की है। आंकड़ों के मुताबिक, लिस्ट में 65,45,679 मतदाताओं (11.81%) को स्थायी रूप से स्थानांतरित पाया गया। इसके अलावा, 19,00,926 मतदाता (3.43%) अपनी जगह पर अनुपस्थित मिले। 16,39,864 मतदाताओं (2.96%) का निधन हो चुका है, जिन्हें मृत के रूप में मार्क किया गया है। वहीं, 7,09,870 मतदाताओं (1.28%) के नाम पहले से ही कहीं और रजिस्टर्ड थे या वो डुप्लीकेट पाए गए।

देशभर में एसआईआर को लेकर को मचा हुआ है बवाल



कर्नाटक में मुख्य चुनाव आयुक्त ने दी दलील

कर्नाटक में मुख्य चुनाव आयुक्त अंबु कुमार ने फाइनल इलेक्टोरल रोल और वोटर एनरोलमेंट पर कहा, '16 जून, 2026 तक इलेक्टोरल रोल में लगभग 5.54 करोड़ वोटर्स में से, लगभग 1.08 करोड़ ड्राफ्ट रोल में शामिल नहीं थे। इसमें लगभग 18 लाख मरे हुए वोटर्स और लगभग 7 लाख डुप्लीकेट वोटर्स शामिल हैं। तो, लगभग 25 लाख वोटर्स या तो मरे हुए थे या डुप्लीकेट थे।'

फॉर्म 6 के जरिए जुड़ सकेंगे नाम

वोटर एनरोलमेंट कैंपेन पर अंबु कुमार ने बताया, 'हमने कई स्पेशल ड्राइव और कैंपेन चलाए हैं और खूब पब्लिसिटी की है। सभी पॉलिटिकल पार्टियों और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने कोऑपरेट किया है। मेरी राय में, कर्नाटक में ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां लोगों को इस मुद्दे के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया गया हो. मेरा मानना है कि हर एलिजिबल वोटर Form 6 का इस्तेमाल करके अप्लाई करेगा।'

200 जिंदा लोगों के नाम गायब, 4 दर्जन मृतकों के नाम दर्ज

अमेठी वोटर लिस्ट विवाद : चंदा जुटाकर हाईकोर्ट पहुंचे ग्रामीण

उत्तर प्रदेश के अमेठी में पंचायत मतदाता सूची की बड़ी धांधली सामने आई है। ग्रामीणों द्वारा लगातार शिकायत किए जाने के बावजूद बीएलओ सर्वे के बाद भी ना तो जिंदा लोगों के नाम जोड़े गए और ना ही मृतकों के नाम काटे गए। दशकों से मतदान कर रहे परेशान ग्रामीणों ने आपस में चंदा जुटाकर न्याय पाने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया। पवन कुमार समेत 137 लोगों ने रिट याचिका संख्या 10808/2026 दायर की है। इसके बाद अब प्रशासनिक अधिकारी जांच-पड़ताल के लिए गांव के चक्कर लगा रहे हैं। पूरा मामला महमूदपुर न्याय पंचायत का है। स्थानीय ग्रामीणों मो. अयाज खान, मो. रेयाज और हालिकुल निशा ने बताया कि वे पिछले 40 सालों से लगातार मतदान करते आ रहे हैं। इस बार अचानक उनके और उनके परिजनों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए, जबकि मृत लोगों के नाम दर्ज हैं। अधिकारियों से बार-बार गुहार लगाने के बाद भी जब कोई सुनवाई नहीं हुई, तो ग्रामीणों को आपस में चंदा इकट्ठा करके कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा।

कांग्रेस ने किया विरोध

इस बीच, कांग्रेस ने इस पूरी प्रक्रिया की कड़ी आलोचना की है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि मतदाताओं की सुरक्षा करना राज्य सरकार और पार्टी का कर्तव्य है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने देशभर में चल रही एसआईआर प्रक्रिया रोकने और CEC ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर की है। उन्होंने प्रक्रिया में गड़बड़ियों का आरोप लगाया है।

रहे युवाओं की आवाज कांग्रेस सरकार ने अनसुनी की: भाजपा

नई दिल्ली/संचार जगत

भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं पूर्व सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव ने मंगलवार को तिरुवनंतपुरम में पीएससी परीक्षा पास कर रैंक हासिल करने के बावजूद नियुक्ति न मिलने पर युवाओं द्वारा पिछले 114 दिनों से सचिवालय के सामने हो रहे प्रदर्शन पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। ज्ञात हो कि बारिश में शेड बनाने की अनुमति नहीं मिलने पर आंदोलनकारी वलारमथी ने बाल मुंडवाकर विरोध जताया। राव ने कांग्रेस, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से वलारमथी से माफी मांगने और युवाओं को न्याय दिलाने की पहल करने की मांग की।

राव ने कहा कि केरलम की राजधानी तिरुवनंतपुरम में कुछ युवा पिछले 114 दिनों से लगातार प्रदेश के सचिवालय के सामने विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं।

उनकी मांग है कि पीएससी (पब्लिक सर्विस कमीशन) की परीक्षा पास करके रैंक हासिल करने के आधार पर उन्हें नौकरी दी जाए, लेकिन उन्हें नियुक्ति नहीं दी जा रही है। केरलम की पब्लिक सर्विस कमीशन भ्रष्टाचार और लेफ्ट तथा कांग्रेस कैडर के लोगों की नियुक्ति के लिए जाना जाता है, लेकिन केरलम के आम युवाओं के लिए शायद वहां कोई जगह नहीं है। ये युवा मांग कर रहे हैं कि जब उन्होंने परीक्षा पास करके रैंक हासिल की है, तो उन्हें नौकरी दी जाए और प्राइमरी स्कूल में शिक्षक के पद पर नियुक्त किया जाए। लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं की गई। बीते दिन, बारिश के दौरान इन युवाओं ने अपने लिए एक शेड बनाने की योजना बनाई, लेकिन पुलिस और वहां के प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी। इसके बाद मजबूर होकर इस आंदोलन से जुड़ी एक प्रमुख महिला ने अपने बाल मुंडवाकर विरोध-प्रदर्शन किया। ये दृश्य बेहद चौंकाने वाले, दर्दनाक और शर्मनाक हैं, लेकिन कांग्रेस को इससे कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती।



भाजपा नेता ने कहा कि हमारा कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से सवाल है कि जिस राज्य में आप बार-बार चुनाव जीतने के लिए जाते हैं, जहां कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, वहां पिछले 114 दिनों से युवा विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या उन युवाओं की आवाज आप तक नहीं पहुंचती है या आप उनकी आवाज सुनना ही नहीं चाहते? क्या आपने कोई ऐसा फिल्टर लगा रखा है कि कांग्रेस शासन वाले राज्यों में हो रहे विरोध-प्रदर्शनों की आवाज नहीं सुनेंगे और केवल वहीं सुनेंगे, जहां आपको राजनीति करनी है? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पहले इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही महिला से माफी मांगें और उन्हें न्याय दिलाने के लिए कम से कम अब सामने आकर पहल करें। यह हमारी मांग है।

नेतन्याहू के गुट और आईडीएफ पूर्व प्रमुख के बीच कड़ा मुकाबला

इजराइल में चुनाव संपन्न, 120 सांसद चुने जाएंगे, 4 को आएंगे नतीजे

नई दिल्ली/संचार जगत

इजराइल में मंगलवार को चुनाव हुए। ये चुनाव 7 अक्टूबर, 2023 को हमास द्वारा किए गए हमले के बाद पहला चुनावी मुकाबला है। मतदान स्थानीय समयानुसार सुबह सात बजे शुरू हुआ और रात 10 बजे समाप्त हुआ। देश की संसद, 26वीं नेसेट के चुनाव के लिए मतदान करते हुए, इजराइलियों ने मंगलवार को शांति की उम्मीद जताई, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का समर्थन किया और इसके भविष्य में विश्वास व्यक्त किया। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू ने भी यरूशलेम के एक मतदान केंद्र पर वोट डाला। इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग और उनकी पत्नी मिशाल हर्जोग, देश के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-गवीर ने भी अपना वोट डाला। पीएम नेतन्याहू के सामने प्रमुख चुनौती पेश कर रहे गादी आइजेनकोट भी मतदान के दिन सक्रिय नजर आए। मतगणना के बाद शुरुआती तस्वीर कुछ घंटों में साफ हो सकती है, लेकिन सरकार बनाने को लेकर स्थिति



पीएम बेंजामिन नेतन्याहू मतदान करते हुए

स्पष्ट होने में समय लग सकता है। अंतिम मतगणना शुक्रवार तक पूरी होने की उम्मीद है, जबकि आधिकारिक नतीजे 4 नवंबर को जारी किए जाने हैं।

देशभर में 12,018 मतदान केंद्र

केंद्रीय चुनाव समिति के कार्यवाहक महानिदेशक डीन लिवने के मुताबिक, देशभर में 12,018 मतदान केंद्र और 18,000 मतपेटियां तैयार की गई हैं। इनमें से 6,209 मतदान केंद्र दिव्यांगों और विशेष जरूरत वाले मतदाताओं के लिए सुलभ बनाए गए। चुनाव की तैयारियों में करीब 1.5 लाख कर्मचारी और अधिकारी शामिल रहे हैं, जिनमें मतदान के दिन तैनात लगभग एक लाख कर्मी भी शामिल हैं। मतदान और मतगणना की निगरानी के लिए करीब 15,000 कैमरे लगाए गए थे।

अमेरिका में मध्यावधि चुनाव

आखिरी पोल में ट्रंप के लिए निराशाजनक संकेत

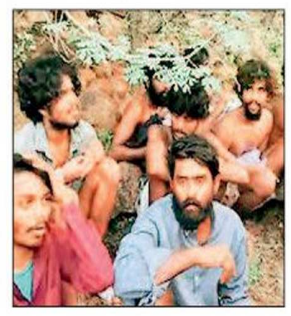
अमेरिका में मध्यावधि चुनावों से एक सप्ताह पहले जो जनमत सर्वेक्षण कराया गया है उससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी को निराशा जरूर होगी। ट्रंप डेमोक्रेट्स से पिछड़ते नजर आ रहे हैं। टैरिफ वॉर और ईरान संघर्ष के कारण अमेरिकी मतदाताओं को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है और पोल परिणाम इसी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं। प्रमुख चुनाव विश्लेषकों का मानना है कि उनकी रिपब्लिकन पार्टी 'हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स' (प्रतिनिधि सभा) पर अपना नियंत्रण खो देगी, जबकि सीनेट के नतीजों को लेकर स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है। वोटिंग पहले ही चल रही है। कुल 21.70 करोड़ पंजीकृत मतदाता। मध्यावधि चुनावों (मिडटर्म इलेक्शन) में आमतौर पर मतदान प्रतिशत कम रहता है। 2022 में यह 46.2 प्रतिशत और 2018 में 50 प्रतिशत दर्ज किया गया था।

तमिलनाडु की घटना

मिर्गी के दौरे का नाटक, गार्डों पर हमला, 17 कैदी हुए फरार

नई दिल्ली/संचार जगत

तमिलनाडु के थेनी जिले की थेक्कमपट्टी सब-जेल से सोमवार देर रात 17 कैदी फरार हो गए। कैदियों ने एक साथी को मिर्गी का दौरा पड़ने का नाटक किया। उसकी मदद के लिए जैसे ही जेलकर्मी सेल में पहुंचे, सभी ने उन पर हमला कर दिया और फरार हो गए। पुलिस ने अब तक 5 कैदियों को गिरफ्तार किया है। बाकी कैदियों की तलाश जारी है। उन्हें पकड़ने के लिए 17 स्पेशल टीमें बनाई गई हैं। आसपास के जिलों में अलर्ट जारी किया गया



है और पड़ोसी राज्य केरल की पुलिस को भी सूचना दी गई है। घटना के बाद ड्यूटी पर तैनात 9 जेलकर्मियों और अधिकारियों को लापरवाही के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है।

स्वामित्व, प्रकाशक एवं संपादक : अवंतिका राठौड़ - पी.के. प्रिंटर्स एंड स्टेशनर्स, 31, राम मंदिर के पास, पटेल नगर, 22 गोदाम, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। कार्यालय : जे-17, रमेश मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर। संपर्क : 0141 463 7668
ई-मेल : sancharjagat@gmail.com| आरएनआई नं. : RAJHIN/2014/55262 समाचार चयन के लिए पीआरबी अधिनियम के तहत जिम्मेदार। न्यायाधिकार क्षेत्र : जयपुर महानगर।